कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/2025-27 RNI No. 1832/57 डाक प्रेषण का दिन - सोमवार, मंगलवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 2 फरवरी 2026 वर्ष - 80 अंक - 23 मूल्य - रु. 12/- कुल पृष्ठ -16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

5

फसल में सल्फर का महत्व

फूलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान दे रही सरकार : डॉ. यादव

गुलाब उद्यान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उद्यानिकी विभाग के ब्रोशर विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। इस अवसर पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, स्थानीय विधायक श्री भगवानदास सबनानी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्णवाल, सचिव उद्यानिकी श्री जॉन किंग्सले एआर उपस्थित थे।

भारत-यूरोपियन यूनियन में समझौता

किसानों, कृषि उत्पादों के लिए खुलेंगे नए अवसरों के द्वार : श्री चौहान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता केवल एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक है।

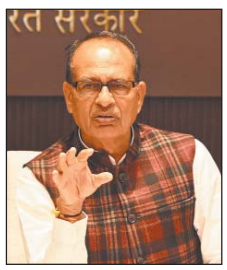

उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद-जैसे चाय, कॉफी, मसाले, टेबल अंगूर, खीरा और अचार वाली खीरा, सूखे प्याज, मीठा मक्का, चुनिंदा फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड को इस समझौते से बड़ा लाभ होगा। प्रमुख क्षेत्रों में आपसी संवेदनशीलता का सम्मान करते हुए यह समझौता निर्यात वृद्धि को घरेलू प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करता है और दोनों पक्षों के किसान समुदायों के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि के लिए यह एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय किसानों, कृषि उत्पादों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। भारत की कृषि शक्ति आज विश्व के सामने है- भारत चावल उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और हमारी कृषि विकास दर ने हरित क्रांति के दौर को भी पीछे छोड़ दिया है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विस्तार से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ यह समझौता कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। इससे भारतीय कृषि उत्पादों को यूरोपीय बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

केंद्रीय बजट 2026-27 के पूर्व एफएआई की मांग

फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मजबूत करने ठोस कदम उठाए सरकार

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले, द फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने सरकार से अपील की है कि देश में खाद की उपलब्धता, संतुलित पोषण और घरेलू उर्वरक उद्योग को मज़बूत करने के लिए ठोस नीतिगत और वित्तीय कदम उठाए जाएँ।

एफएआई ने कहा कि वर्ष 2024-25 में भारत ने 358 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है, जिसमें खाद की अहम भूमिका रही है। आने वाले वर्षों में इस उत्पादन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि खाद का सही और संतुलित उपयोग हो।

किसानों और उद्योग के बीच संतुलन जरूरी

एफएआई के महानिदेशक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि खाद सुरक्षा तभी संभव है जब किसानों को उचित कीमत पर खाद मिले, उद्योग आर्थिक रूप से मजबूत रहे और नए निवेश लगातार होते रहें।

देश में खाद उत्पादन बढ़ाने पर जोर

एफएआई ने सरकार से देश में फॉस्फेट और पोटाश आधारित खाद के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की माँग की है। इसके तहत नई फैक्ट्रियाँ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स और विदेशों में कच्चे माल के रणनीतिक निवेश को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

कर और GST व्यवस्था में सुधार की मांग

एफएआई ने खाद उद्योग पर पड़ने वाले कर बोझ को कम करने की भी मांग की है। इसमें अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और सल्फर जैसे कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी घटाने या हटाने, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में राहत और उलटी GST से जुड़ी समस्याओं के समाधान की बात शामिल है।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

कृषि- पशुपालन क्षेत्र के पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2026

नई दिल्ली (कृषक जगत)। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कृषि, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों के प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिनमें 2 युगल पुरस्कार (युगल पुरस्कार को एक ही माना जाता है) शामिल हैं, सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।

डॉ. ए.के. सिंह : बासमती चावल की 25 उन्नत किस्मों के जनक

चावल और बासमती प्रजनन के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान के लिए डॉ. ए.के. सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह पादप आनुवांशिकी के विशेषज्ञ हैं और लगभग तीन दशकों तक ICAR-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) से जुड़े रहे। IARI के पूर्व निदेशक रहे डॉ. सिंह ने बासमती चावल की 25 उन्नत किस्मों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनकी विकसित किस्मों से हर साल करीब 50 हजार करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित हो रहा है।

डॉ. गोपाल जी त्रिवेदी : लीची उत्पादन में क्रांति

बिहार के डॉ. गोपाल जी त्रिवेदी को पारंपरिक ज्ञान आधारित खेती और कृषि विस्तार सेवाओं में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। उन्होंने लीची के पुराने बागानों में कैनोपी मैनेजमेंट तकनीक को अपनाया, जिससे पेड़ों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और किसानों की आय दोगुनी हो गई। उन्होंने जल-जमाव वाले इलाकों में मखाना और सिंघाड़े की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से बिहार कृषि नवाचारों का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है।

डॉ. के. रामासामी : टिकाऊ और प्राकृतिक खेती के अग्रदूत

तमिलनाडु के डॉ. के. रामासामी को टिकाऊ खेती और किसान-नेतृत्व वाले नवाचारों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, फर्टी-इरिगेशन, बायोगैस और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई।

डॉ. रामासामी ने 30 से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिससे वैज्ञानिक शोध सीधे खेतों तक पहुंचा और किसानों को व्यावहारिक लाभ मिला।

डॉ. प्रेम लाल गौतम : पादप आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षक

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को पादप आनुवांशिकी, फसल सुधार और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। उन्होंने पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ भारतीय कृषि शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्रीरंग देवबा लाड : कपास उत्पादन में 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी

महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसान और इनोवेटर श्रीरंग देवबा लाड को कपास खेती में नवाचारों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी विकसित 'दादा लाड कपास तकनीक' से बीज कपास की पैदावार में 300 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई। इस तकनीक से हजारों किसानों की आय में 40 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ है।

श्री जोगेश देउरी : मूगा रेशम से संवारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

असम के जोगेश देउरी को जमीनी स्तर पर कृषि और आजीविका सुधार के लिए पद्मश्री मिला है। उन्होंने विश्व-प्रसिद्ध मूगा रेशम के संरक्षण और संवर्धन में अहम योगदान दिया। पारंपरिक रेशम कीट पालन को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़कर उन्होंने हजारों परिवारों के लिए टिकाऊ आजीविका मॉडल तैयार किया।

श्री रघुपत सिंह : खेती-बाड़ी के पंडित (मरणोपरांत)

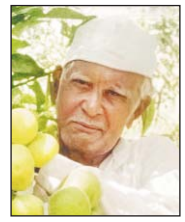

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के किसान रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने राजमा की 23 उन्नत किस्में विकसित कीं और लगभग विलुप्त हो चुकी 55 से अधिक सब्जियों की किस्मों को फिर से जीवित किया। उनके शोध से करीब 100 नई पौध प्रजातियां सामने आईं, जिनमें 1.5 मीटर लंबी लौकी भी शामिल है।

श्री राम रेड्डी मामिडी : सहकारी समितियों से बदली ग्रामीण आजीविका (मरणोपरांत)

तेलंगाना के राम रेड्डी मामिडी को पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी ग्रामीण आजीविका प्रणालियों को मजबूत करने के लिए मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों के जरिए किसानों को प्रशिक्षण दिया और महिला-नेतृत्व वाली संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया।

आर्थिक समीक्षा में कृषि की उजली तस्वीर!

● मधुकर पवार,मो.: 8770218785

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा गत 29 जनवरी को संसद में प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा 2025-26 से यह स्पष्ट हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती में कृषि और ग्रामीण भारत की भूमिका बरकरार है। आर्थिक समीक्षा में कृषि उत्पादन और सहयोगी क्षेत्रों की प्रगति को दर्शाते हुए बताया गया है कि बीते वर्षों में बुनियादी ढांचे, तकनीक और नीति सुधारों ने गांवों की तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्थिक समीक्षा में कृषि क्षेत्र के आंकड़े उत्साहजनक हैं। पिछले पांच वर्षों में कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों की औसत वार्षिक विकास दर 4.4 प्रतिशत रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई। दशकीय (2016-25) औसत वृद्धि दर 4.45 प्रतिशत रही, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पशुधन (7.1 प्रतिशत) और मत्स्य पालन (8.8 प्रतिशत) जैसे सहयोगी क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से संभव हुई है।

देश में खाद्यान्न उत्पादन भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाजों की बेहतर उपज इसका मुख्य कारण रहा है। बागवानी क्षेत्र, जो कृषि सकल मूल्य वर्धन में 33 प्रतिशत योगदान देता है, 2024-25 में 362 मिलियन टन से अधिक उत्पादन के साथ खाद्यान्न उत्पादन से आगे निकल गया। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक और फल-सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने बीज, सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, यंत्रीकरण और विपणन अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। 6.85 लाख बीज ग्राम, 25.55 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 25,689 कस्टम हायरिंग सेंटर, ई-नाम पर 1.79 करोड़ किसानों का पंजीकरण और 10 हजार एफपीओ का गठन-ये सभी तथ्य बताते हैं कि कृषि को एक संगठित और बाजारोन्मुख क्षेत्र बनाने की कोशिश जारी है।

मूल्य और आय समर्थन के तहत एमएसपी, पीएम-किसान और कृषि ऋण योजनाओं ने किसानों को स्थिरता दी है। पीएम-किसान के तहत अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में पहुंचाए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025 में कृषि ऋण वितरण 28.69 लाख करोड़ रुपये रहा।

पशुधन क्षेत्र ने 2015 से 2024 के बीच उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके सकल मूल्य वर्धन में लगभग 195 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 12.77 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-25 के दौरान मछली उत्पादन में 140 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।

आर्थिक समीक्षा का पहला मजबूत पक्ष ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विस्तार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई पहल ने ग्रामीण संपर्क में क्रांतिकारी बदलाव किया है। 15 जनवरी 2026 तक 99.6 प्रतिशत पात्र बसावटों को ऑल-वेदर सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की भूमिका भी अहम रही है। योजना के तहत 2029 तक 4.95 करोड़ पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

जल जीवन मिशन ने 'हर घर जल' के लक्ष्य को वास्तविकता के करीब पहुंचाया है। अगस्त 2019 में योजना की शुरुआत के समय केवल 17 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध था। 20 नवंबर 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 81.30 प्रतिशत यानी 15.74 करोड़ ग्रामीण घरों तक पहुंच गया।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 कृषि और ग्रामीण भारत की एक तथ्यपरक और आशावादी तस्वीर पेश करती है। लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही है। किसानों को न तो समय पर खाद मिलती है और न ही पर्याप्त बिजली। नकली खाद और बीज से भी किसानों की उम्मीदों पर तुषारापात हो जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य अपनी उपज को बेचने के लिए तरस जाते हैं जबकि सरकार भी जानती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने पर किसानों की लागत की भी भरपाई नहीं हो पाती है। अब उम्मीद यह है कि इन उपलब्धियों के साथ किसानों की ज्वलंत समस्याओं जैसे खाद और बिजली की समय पर उपलब्धता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की बिक्री, लागत कम करने के उपाय, फसल बीमा के तहत मुआवजा का सही आकलन और शीघ्र भुगतान तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाने पर गम्भीरता से विचार कर कार्यान्वयन करना चाहिए। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन, जलवायु-संवेदनशील नीतियाँ और बाजार सुधारों को प्राथमिकता देना होगा। यदि ऐसा होता है, तो कृषि न केवल 'विकसित भारत' के लक्ष्य की धुरी बनेगी, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायी सुधार का आधार सिद्ध होगी।

प्रदेश के 1.17 लाख सोयाबीन किसानों को मिली 200 करोड़ की भावांतर राशि

भोपाल (कृषक जगत)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के किसानों के कल्याण के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करते हुए अन्नदाता सम्मान समारोह में प्रदेश के 1 लाख 17 हजार किसानों को सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की राशि दी। यह राशि किसानों के खातों में जमा की गई, जिनमें मंदसौर जिले के भी किसान शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना में अब तक 7 लाख 10 हजार से अधिक किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। इस योजना के तहत मंदसौर जिले के 27 हजार से अधिक किसानों को करीब 43 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

भावांतर योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में और योजनाओं का ऐलान करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में सरसों और मूंगफली की फसलों को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लाया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिले।

कपास उत्पादन में नई पहल

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कपास उत्पादक किसानों के लिए पीएम मित्र पार्क के शुरुआत की घोषणा की, जो देश में अपनी तरह का पहला पार्क होगा। इससे 6 लाख किसानों को लाभ होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

इस सम्मान समारोह में उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और किसान बंधुओं के अलावा बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें भी उपस्थित थीं।

बेमौसम बरसात-ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

प्रदेश के किसानों पर इस समय मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। गत दिनों अचानक बदले मौसम ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मसूर और सरसों सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने असमय वर्षा, मावठा के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ-साथ मौसम अस्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, एक साथ सक्रिय हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ सिस्टम के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। गत मंगलवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, देवास, शिवपुरी, शाजापुर, खरगोन, गुना और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओले भी गिरे।

मुख्यमंत्री ने दिए कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने असमय वर्षा के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश के हर जिले में प्रशासन असमय वर्षा, मावठे के प्रति सतर्क रहे। जिला प्रशासन किसानों को असमय वर्षा से होने वाली क्षति से बचाने का प्रयास करे।

खड़ी फसल को भारी नुकसान

इस बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों जैसी रबी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। तेज हवाओं के कारण कई खेतों में फसल जमीन पर गिर गई, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ने की आशंका है।

श्री रघुवंशी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल बने

भोपाल। श्री आर. एस. रघुवंशी मध्यप्रदेश परिमंडल के नए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल बने। उन्होंने गतदिनों अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री रघुवंशी भारतीय डाक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी हैं तथा वे जोधपुर, राजस्थान से स्थानांतरित होकर मध्यप्रदेश परिमंडल में पदस्थ हुए हैं। डाक सेवाओं के विस्तार, सेवाओं में सुधार तथा विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिए पंजीयन 7 फरवरी से

भोपाल (कृषक जगत)। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये अधिक है।

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसानों को एसएमएस कर जानकारी भी दी जाएगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्द्रिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराड़े,** फोन : 0755-4248100, 2554864, फैक्स : 0755-2571449. E-mail-info@krishakjagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/-.भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्दिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

आनंद वह वस्तु है जिसे मांगने पर पछताना नहीं पड़ता।
- सुकरात

मावठा और ओलावृष्टि : अवसर, चेतावनी और किसान की सजगता

प्रकृति की हर मेहरबानी अपने साथ कुछ अवसर लाती है, तो कुछ कठोर संदेश भी छोड़ जाती है। हाल की मावठे की वर्षा ने जहाँ रबी फसलों के लिए नई उम्मीद जगाई है, वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मौसम का असंतुलन कितनी तेजी से लाभ को नुकसान में बदल सकता है। कृषि, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सबसे पहले और सबसे अधिक इसी अनिश्चितता का सामना करती है।

मावठे की बारिश विशेष रूप से असिंचित क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है। प्रदेश में खेती का बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित है और इस समय मिली नमी यदि सही ढंग से उपयोग में लाई जाए तो गेहूं, चना, मसूर और अन्य रबी फसलों की पैदावार में सुधार संभव है। लेकिन ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों ने यह भी याद दिलाया है कि केवल उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है।

देश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया है। गेहूं की बालियों, चने और अरहर की फलियों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। यह स्थिति बताती है कि बदलते मौसम में चरम घटनाएँ- जैसे ओला, पाला या असमय वर्षा—अब अपवाद नहीं रहीं। ऐसे में फसल बीमा, समय पर

सर्वे और त्वरित राहत व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्षा के बाद मौसम के साफ होते ही पाले की आशंका भी बढ़ जाती है। विशेषकर अरहर की फसल, जो फूल अवस्था में होती है, पाले से सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है। वहीं आलू की फसल में नमी और ठंडक का यह संयोग पिछेती झुलसा रोग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे समय पर फफूंदनाशी छिड़काव की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।

गेहूं की फसल के लिए गेरूआ रोग की चुनौती भी कम गंभीर नहीं है। मावठे के जल और हवा के साथ पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली फफूंदियाँ अभी भले ही शांत हो, लेकिन तापमान अनुकूल होते ही उनका प्रसार तेजी से हो सकता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूरे और काले गेरूए का खतरा विशेष सतर्कता की माँग करता है।

खेती आज केवल मेहनत का विषय नहीं रही, बल्कि समझ और तैयारी का भी प्रश्न बन चुकी है। किसान को अब मौसम की हर करवट पर नजर रखनी होगी और वैज्ञानिक सलाह को अपनाना होगा। ओलावृष्टि से मिले घाव यह सिखाते हैं कि प्रकृति की कृपा के साथ उसकी कठोरता के लिए भी तैयार रहना जरूरी है।

अंततः मावठा हो या ओलावृष्टि—दोनों प्रकृति के संकेत हैं। यदि इन संकेतों को समय रहते समझा जाए, तो नुकसान को सीमित कर लाभ की संभावनाएँ बढ़ाई जा सकती हैं। जागरूक किसान, सक्रिय प्रशासन और समय पर निर्णय ही खेती को इन अनिश्चितताओं के बीच टिकाऊ और लाभकारी बना सकते हैं।

नीलगाय और जंगली सुअर : खेती और नीति की समस्या

● अरविंद सरदाना

नीलगाय और जंगली सुअर से फसलों को बड़े पैमाने पर हो रहे नुकसान से किसान परेशान हैं और खेती- किसानी को जानने- समझने वाले लगभग सभी लोग इस समस्या से वाकिफ हैं। इस समस्या के निदान में कई भ्रांतियाँ बाधक बनी हैं। मसलन- यह भ्रम बना हुआ है कि इन जानवरों का आवास जंगल में है जो कि सही नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार 85 प्रतिशत नीलगायों का आवास राजस्व क्षेत्र में है।

गाँव के आसपास की चरनोई ज़मीन और वहाँ की झाड़ियों के बीच इनका डेरा रहता है। वहाँ से वे अपना पेट भरने के लिए खेतों में आ जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं। नीलगायों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। एक रपट के अनुसार मध्यप्रदेश के अकेले शाजापुर जिले में नीलगायों की संख्या लगभग 2000 और कुछ अन्य जिलों में 6000 है। मध्यप्रदेश के ऐसे 21 जिले हैं, जिन्हें वन विभाग ने समस्याग्रस्त बताया है। इन जिलों के राजस्व क्षेत्र में नीलगायों की संख्या हजारों में होने की सम्भावना है।

एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब एक लाख नीलगायें हैं और इनका बड़ा हिस्सा मध्यप्रदेश में है जहां पुराना अनुमान 33,500 का बताया जाता है। जंगल को बचाने के लिए इन्हें 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972' में जोड़ा गया था, किन्तु जब नीलगाय की मौजूगी राजस्व क्षेत्र में होने की बात सामने आई तो यह स्वतः ही 'वन्यजीव संरक्षण कानून' की परिधि से बाहर हो गई। एक नीलगाय को प्रतिदिन 18 से 30 किलो हरा चारा चाहिए जो चरनोई की घास एवं खेती को नष्ट करके ही प्राप्त हो सकता है। एक जिले में जहाँ 6000 नीलगाय हैं, वहाँ इनसे लगभग 4000 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित होती है।

इस तथ्य का पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि वन विभाग को मध्यप्रदेश के 21 जिलों और

34 चिन्हित ब्लाकों, जो उनकी रपट के अनुसार सबसे प्रभावित इलाके हैं, में सघन सर्वे करके नीलगाय और जंगली सुअर की गणना की जाए। इसमें ग्राम पंचायत और किसानों का पूरा सहयोग लिया जाए। सर्वे के माध्यम से नीलगायों के डेरों को मानचित्र पर उतारा जाना चाहिए और उनका प्रभाव क्षेत्र एवं संख्या नोट की जानी चाहिए।

समस्या के निदान का एक तरीका हो सकता है कि नीलगायों को राजस्व क्षेत्र से पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। कई कारणों से यह कारगर नहीं है। हाल में शाजापुर जिले में स्थानांतरण का एक प्रयोग किया गया था। यह साउथ अफ्रीका की 'बोमा तकनीक' है। एक बागड़ बनाकर रास्ता निकाला जाता है जहाँ से हिरण एवं नीलगाय को हेलीकाप्टर की मदद से जंगल की ओर भगाया जाता है। इस तरह से केवल 67 नीलगायों को हकाला जा सका, जबकि उनकी संख्या हजारों में है। यदि स्थानांतरण संभव भी हो, तब भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वन्यजीवों की बड़ी संख्या के पोषण की आपूर्ति जंगल नहीं कर सकता। जंगल के संसाधनों को

नीलगायों और जंगली सुअरों का फसलों को चौपट करने के लिए खेतों में उतरना एक तरह से कथित 'वैज्ञानिक वानिकी' का ही नतीजा है। कई इलाकों में वन्यप्राणियों के वन-निवासियों से घातक द्वंद्व भी इसी पद्धति से उपजे हैं। इनसे आखिर कैसे निपटा जा सकता है?

देखते हुए एक सीमित मात्रा में स्थानांतरण किया जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि जंगल में चरनोई एवं पानी की व्यवस्था बढ़ाई जाए, ताकि इस प्रकार के वन्यजीवों के लिए पर्याप्त पोषण हो सके।

नीलगाय एवं जंगली सुअर की विशाल संख्या, जिन्होंने गौचर भूमि पर दशकों से डेरा बना लिया है, को कम करने का एक ही तरीका हो सकता है। 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' में प्रावधान है कि चिन्हित इलाकों में नीलगाय एवं जंगली सुअर को 'वर्मिन' यानी नुकसानदायक जानवर घोषित किया जाए। यह एक निश्चित समय के लिए लागू होता है। ऐसा करने पर वन विभाग, अपने नियंत्रण में उनकी संख्या को कम करने की योजना बना सकता है। वह शिकारियों की टीम गठित कर सकता है और एक योजना के तहत इसे अंजाम दे सकता है।

इसी प्रकार की योजना बिहार में लागू की गई थी और सफल रही। वर्ष 2015 में क़ानूनी अनुमति के बाद नीलगाय और जंगली सुअर को 'वर्मिन' घोषित किया गया। यह बिहार के 31 जिलों में लागू किया गया था। एक अनुमान है कि लगभग दस हज़ार नील गायों को मारा गया। इस प्रक्रिया में पंचायतों की लिखित शिकायत पर जांच करके वन विभाग ज़रूरत पड़ने पर शिकारियों की व्यवस्था करता है। वर्ष 2016 में उत्तराखंड सरकार ने जंगली सुअरों को मारने की अनुमति ली। इस प्रकार की अनुमति 'मुख्य वन्यप्राणी वार्डन' द्वारा विशेष परिस्थितियों में दी जाती है और कई राज्यों ने इसका उपयोग किया है।

इस समय मध्यप्रदेश के लिए एक विशेष अभियान की ज़रूरत है क्योंकि यह वन्यजीव जंगल के बाहर बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। मुआवजा देकर या बागड़ बनाकर इसका हल निकालना समस्या को टालने वाला कदम होगा। अभी तक मुआवजे का रिकॉर्ड नगण्य रहा है और नीलगाय आसानी से बागड़ लांघ जाते हैं। पानी सर के ऊपर हो जाने से पहले कदम उठाना समझदारी होगी।

इसकी रोकथाम से खेती पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज किसानों ने कई फसलें लगाना छोड़ दिया है जिन्हें नीलगाय या जंगली सुअर के झुण्ड रातों-रात नष्ट कर देते हैं, जैसे-चना, मक्का, तुअर, मूंगफली, सब्जियाँ आदि। हम मिश्रित खेती की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए भी इस समस्या का निदान ज़रूरी है। आवश्यक है कि नीलगाय एवं जंगली सुअर की समस्या को केवल संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि 'मानव - वन्यजीव प्रबंधन' के रूप में देखा जाए। 'वर्मिन' घोषित करने जैसे निर्णयों के साथ प्रशिक्षित शिकारी और वन विभाग की सीधी जवाबदेही तय करना आवश्यक है। **(सप्रेस)**

फसल में सल्फर का महत्व

● अनामिका तोमर, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर

सल्फर, जो कि मृदा पोषण में चौथा आवश्यक तत्व है, जिस पर किसान प्रायः ध्यान नहीं देते हैं, तिलहनी फसलें भारतीय आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसका उत्पादन लगभग 24 मिलियन टन हो रहा है। तिलहन फसल के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग आवश्यक है, जिसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक, जिंक व बोरान तत्व अति आवश्यक है। गत वर्षों में संतुलित उर्वरकों के अंतर्गत केवल नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर बल दिया गया। सल्फर के उपयोग पर विशेष ध्यान न दिये जाने के कारण मृदा के नमूनों में 40 प्रतिशत गंधक (सल्फर) की कमी पाई गई। आज उपयोग में आ रहे गंधक रहित उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश के उपयोग से गंधक की कमी निरंतर बढ़ रही है।

फसल की अच्छी उपज के लिए हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिना उर्वक के फसल की अच्छी उपज होना मुश्किल है। ऐसे में खेती के लिए सबसे बड़ी जरूरत सही उर्वरक का चयन है। खेती के लिए किस प्रकार की उर्वरक लाभदायी होगी उसकी कैसे पहचान करें ये जानना बहुत जरुरी है।

गंधक की कमी मुख्यतः निम्न कारणों से भूमि के अंदर हो जाती है, जिसकी तरफ कृषकों का ध्यान नहीं जाता-

● भूमि में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग न करना।

● लगातार विभिन्न फसलों द्वारा गंधक जमीन में लेते रहने व सल्फर रहित उर्वरकों के प्रयोग में इन तत्वों की कमी हो जाती है।

● ऐसे उर्वरकों का उपयोग जिसमें बहुत कम या न के बराबर सल्फर का होना।

● जहाँ अकार्बनिक खादें प्रयोग में नहीं आती है, वहाँ पर भी सल्फर की कमी का होना।

● हाल ही में तोड़ कर विकसित की गई भूमि या हल्क गठन वाली बलुई मिट्टी में, जहाँ निक्षालन द्वारा पोषक तत्वों की हानि हो जाया करती है, सल्फर की कमी पाई जा सकती है।

सल्फर की कमी के लक्षण

● सल्फर की कमी से पौधों का रंग पीला हो जाता है और इस कमी की शुरुआत पौधों के ऊपरी हिस्से या नये पत्ते से होती है।

● सल्फर की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है।

● पौधों का हरापन कम हो जाता है।

● खाद्यान्न फसलें अपेक्षाकृत देर से पकती हैं एवं बीज ढंग से परिपक्व नहीं हो पाते हैं।

● पत्तियां व तने में बैंगनीपन आ जाता है।

● गंधक के अभाव में पौधे पीले, हरे, पतले और आकार में छोटे हो जाते हैं तथा पौधे का तना पतला और कड़ा हो जाता है।

● सल्फर की कमी से आलू की पत्तियों का रंग पीला, तने कठोर तथा जड़ों का विकास कम रहता है। सल्फर की कमी से फसल में फूल नहीं आते और न ही फल बनते हैं।

गंधक के कार्य

● गंधक क्लोरोफिल का अवयव नहीं है फिर भी यह इसके निर्माण में सहायता करता है तथा पौधे के हरे भाग की अच्छी वृद्धि करता है।

● यह गंधक युक्त एमिनो अम्लों, सिस्टाइन, सिस्टीन तथा मिथियोनीन तथा प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक होता है।

● सरसों के पौधों की विशिष्ट गंध निर्माण को यह प्रभावित करती है। तिलहनी फसलों के पोषण में गंधक का विशेष महत्व है क्योंकि बीजों में तेल बनने की प्रक्रिया में इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

● सरसों के तेल में गंधक के यौगिक पाये जाते हैं। तिलहनी फसलों में तैलीय पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करती है।

● इसके प्रयोग से बीज बनने की क्रियायों में तेजी आती है।

गंधक की कमी को दूर करना

गंधक की कमी गंधक युक्त निम्नलिखित उर्वरकों के प्रयोग से दूर की जा सकती है।

उर्वरक	उपलब्ध गंधक (प्रतिशत)	प्रयोग विधि
सिंगल सुपर फास्फेट	12	बुवाई के पूर्व बेसल ड्रेसिंग के रूप में
पोटैशियम सल्फेट	18	बुवाई के पूर्व बेसल ड्रेसिंग के रूप में
अमोनिमयम सल्फेट	24	बुवाई के पूर्व बेसल ड्रेसिंग के रूप में एवं खड़ी फसल में टाप ड्रेसिंग के रूप में।
जिप्सम (शुद्ध)	18	भूमि की सतह पर उचित नमी की दशा में बुवाई में 3-4 सप्ताह पूर्व प्रयोग करें। यह ऊसर भूमि के लिए ज्यादा उपयुक्त है
पाइराइट	22	भूमि की सतह पर उचित नमी की दशा में बुवाई में 3-4 सप्ताह पूर्व प्रयोग करें। यह ऊसर भूमि के लिए ज्यादा उपयुक्त है
जिंक सल्फेट	18	जस्ते की कमी वाली भूमि के लिए उपयुक्त है। इसका प्रयोग बुवाई के 3-4 सप्ताह पूर्व या खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव करें।
तात्विक गंधक	95-100	जिस भूमि में वायु का संचार अच्छा हो तथा चिकनी मिट्टी (भारी भूमि) के लिए विशेष उपयुक्त है। बुवाई के 3-4 सप्ताह पूर्व उचित नमी की दशा में प्रयोग करें।

इन उर्वरकों में गंधक, सल्फेट के रूप में पाया जाता है, जिसका उपयोग पौधे सुगमता पूर्वक कर लेते हैं।

कृषक जगत
डायरी - 2026
बुकिंग प्रारंभ
नए आकार, नए कलेवर में
(एग्जीक्यूटिव डायरी)

कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए संदर्भ ग्रंथ
वर्ष भर कृषि सेवाओं और उत्पादों के
प्रचार हेतु सर्वोत्तम माध्यम

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान कृषि पर विशेष जानकारी
विज्ञापन एवं डायरी खरीदी के लिए संपर्क करें
• इंदौर - सचिन बोन्द्रिया : 9826021837 • भोपाल - अजय बोन्द्रिया : 9826255861
• इंदौर कार्यालय : 9826024864 • रायपुर - प्रेमप्रकाश सुल्लेरे : 9826255862
• नई दिल्ली व जयपुर - निमिष गंगराड़े : 7387422952
• ई-मेल : info@krishakjagat.org • वेबसाइट : www.krishakjagat.org

संतरे की उन्नत खेती

भारत में केले के पश्चात नींबू प्रजाति के फलों का तीसरा स्थान है इसमें सर्दी तथा गर्मी सहन करने की क्षमता होने के कारण नींबू प्रजाति का कोई ना कोई फल लगभग सभी प्रांतों में उगाया जाता है। इन नींबू वर्गीय फलों में संतरा भी एक महत्वपूर्ण फल है। संतरे को वानस्पतिक रूप से सिट्रस रिटीकुलेटा के नाम से जाना जाता है। भारत में नींबू प्रजाति के फलों में संतरे का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इसे मेंडेरीन भी कहते हैं। संतरा अपनी सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ–साथ इसमें विटामिन 'ए' और 'बी' भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। देश के अंदर संतरे का कुल क्षेत्रफल 4.28 लाख हेक्टेयर है जिससे 51.01 लाख टन उत्पादन होता हैं।

● दुर्गाशंकर मीणा, तकनीकी सहायक,
● डॉ. मूलाराम, सहायक आचार्य
● जयराज सिंह गौड़
● मुकुट बिहारी, कृषि पर्यवेक्षक
कृषि अनुसंधान केंद्र, मण्डोर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
Email:-dstameena1997@gmail.com

भूमि

संतरे की खेती लगभग सभी प्रकार की अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त भूमि में की जा सकती है, परंतु गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि की गहराई 2 मीटर हो। मृदा का पीएच 4.5 से 7.5 उचित रहता है। इसकी सफलतम खेती के लिए अवमृदा कंकरीली पथरीली व कठोर नहीं होनी चाहिए।

उन्नत किस्में

भारत में उगाई जाने वाली किस्मों में नागपुरी संतरा, खासी संतरा, कुर्ग संतरा, पंजाब देसी, दार्जिलिंग संतरा व लाहौर लोकल आदि प्रमुख हैं। भारतीय संतरा में नागपुर संतरा सर्वोपरि हैं एवं विश्व के सर्वोत्तम संतरा में इसका स्थान प्रमुख हैं। किंग तथा विलोलीफ के संकरण से तैयार किन्नों की किस्म पंजाब और राजस्थान में व्यवसायिक महत्व की किस्म है।

प्रवर्धन

संतरे का वानस्पतिक प्रवर्धन कलिकायन विधि द्वारा किया जाता है। कलिकायन के लिये मूलवृन्त के रूप में जट्टी खट्टी, जम्भिरी, रंगपुर लाइम, किलओप्टरा मेन्डेरिन, ट्रायर सिट्रेन्ज तथा करना खट्टा काम में लेते हैं। मूलवृन्त फरवरी माह मे तैयार किये जाते है। लगभग एक वर्ष आयु का मूलवृन्त कलिकायन के लिये उपयुक्त रहता है। साधारणतः शील्ड एवं पैच कलिकायन फरवरी से मार्च व सितम्बर – अक्टूबर में किया जाये।

पौधा रोपण

कलिकायन किये गये पौधे दूसरे वर्ष जब लगभग 60 सेमी. के हो जाये तो पौधारोपण हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। संतरे के पौधे लगाने के लिए 90 घन सेमी. आकार के गड्ढे मई–जून में 6×6 मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं। उत्तरी भारत में पौधे लगाने का उचित समय जुलाई–अगस्त है। पौधा लगाने से पूर्व प्रत्येक गड्ढे को 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट व मिट्टी के मिश्रण से भरें। दीमक के नियंत्रण के लिए मिथाइल पेराथियान 50–100 ग्राम प्रति गड्ढा दें।

गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा दिसम्बर–जनवरी में दें। यूरिया की 1/3 मात्रा फरवरी में फूल आने के पहले तथा शेष 1/3 मात्रा अप्रेल में फल बनने के बाद और शेष मात्रा अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह में देवें। संतरा में फरवरी व जुलाई माह में गौण तत्वों का छिड़काव करना उचित रहता है। इसके लिये 550 ग्राम जिंक सल्फेट, 300 ग्राम कॉपर सल्फेट, 250 ग्राम मैंगनीज सल्फेट, 200 ग्राम मैग्नेशियम सल्फेट, 100 ग्राम बोरिक एसिड, 200 ग्राम फेरस सल्फेट व 900 ग्राम चूना लेकर 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

सिंचाई

सर्दी में दो सप्ताह व गर्मी में एक सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। फल लगते समय पानी की कमी से फ्ल झड़ने लगते हैं। फल पकने के समय पानी की कमी से फ्ल सिकुड़ जाते है व रस की प्रतिशत मात्रा घट जाती है। अतः जब सन्तरे का उद्यान फलन में हो तब आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। खाद देने के बाद सिंचाई करना परम आवश्यक है। कटाई–छंटाई संतरे का सुन्दर ढांचा बनाने के लिए प्रारम्भिक वर्षो मे कटाई–छंटाई की जाती है। फल देने वाले पौधो को कटाई–छंटाई की कम आवश्यकता होती है, परन्तु सूखी व रोगग्रस्त टहनियों को काटते रहें।

उपज एवं भण्डारण

कलिकायन द्वारा तैयार किये गये पौधे 3–5 वर्ष की आयु में फल देते हैं। प्रायः पुष्पन के 8 से 9 माह बाद फल पक कर तैयार हो जाते है। संतरे के फलों का रंग हल्का पीला हो जाये तब इन्हें तोड़ लें। 600 से 800 फल तथा औसतन 70 से 80 किग्रा. प्रति पौधा प्राप्त होती है। संतरा के फलों को 5–6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम व 85–90 प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता पर 4 महीने तक भण्डारित किया जा सकता है।

फलों का गिरना

सामान्यतः माल्टा में तुड़ाई के लगभग पांच सप्ताह पहले से फ्ल गिरने लगते हैं, इसकी रोकथाम हेतु 2, 4–डी (10 पीपीएम) या एनएए150 पीपीएम) का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त फलन के समय भूमि में समुचित नमी बनाये रखें।

यदि फलन के समय किसी कवक जनित रोग का प्रकोप हो तो उसके नियंत्रण का उचित उपाय करना लाभकारी रहता है।

खाद एवं उर्वरक

संतरे के पौधों से उत्तम गुणवत्ता वाले अधिक फल प्राप्त करने के लिये खाद व उर्वरकों का उचित प्रबंधन करें। संतरे के पौधो में निम्न सारणी अनुसार खाद व उर्वरक देने की अनुशंसा की जाती है।

पौधे की आयु	गोबर खाद (कि.ग्रा.)	यूरिया (ग्राम)	एसएसपी (ग्राम)	एमओपी (ग्राम)
एक वर्ष	15	125	250	–
दो वर्ष	30	250	500	–
तीन वर्ष	45	375	750	200
चार वर्ष	60	500	600	200
पाँच वर्ष	75	625	1250	400

कीट

नींबू की तितली– तितली की लटें पत्तियों

को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिये लटों को पौधों से पकड़ कर मिट्टी के तेल में डालें। क्विनालफास 25 ई.सी. का 1.5 मिली./लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

फल चूसक – कीट फलों से रस चूस कर नुकसान करता है। प्रभावित फल पीला पड़कर सूख जाता है और गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिये मैलाथियॉन 50 ई.सी. 1 मिली./लीटर पानी का घोल का छिड़काव करें। कीट को आकर्षित करने के लिये प्रलोभक का भी उपयोग करना चाहिए। प्रलोभक में 100 ग्राम शक्कर के 1 लीटर घोल में 10 मिली. मेलाथियॉन मिलाया जाता है।

लीफ माइनर – यह कीट वर्षा ऋतु में नुकसान पहुंचाता है। यह पत्तियों की निचली सतह को क्षतिग्रस्त कर पत्तियों में सुरंग बनाता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटॉन 25 ई.सी. या क्विनालफास 25 ई.सी. का 1.5 मिली./लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें।

मूलग्रन्थी (सूत्रकृमि) – यह नींबू प्रजाति के फलों की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है। इसके प्रकोप से फल छोटे व कम लगते हैं। नुकसान पहुंचाता है जिससे पत्तियाँ पीली पड़ कर टहनियाँ सूखने लगती इसके नियंत्रण के लिये कार्बोफ्यूरॉन 3 जी. 20 ग्राम/पौधा देना चाहिए।

व्याधियाँ

नींबू का केंकर – यह रोग जेन्थोमोनास

सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है। रोग से प्रभावित पत्तियों, फलों व टहनियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते है। फलों पर पीले, खुरदरे धब्बे बन जाने से गुणवत्ता प्रभावित होती है। कागजी नींबू इससे ज्यादा प्रभावित होते है। केंकर की रोकथाम के लिये 20 ग्राम एग्रोमाइसीन अथवा 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। नये रोग रहित पौधों का चुनाव करें तथा पौधों पर रोपण से पूर्व 4:4:50 बोर्डो मिश्रण छिड़कें।

गमोसिस – यह तना सड़न रोग है जिसमें तने से भूमि के पास व टहनियों के ग्रसित भाग से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। इस गोंद से छाल प्रभावित होकर नष्ट हो जाती है। रोग के अधिक प्रकोप से पौधा नष्ट हो जाता है। रोग के नियंत्रण के लिये छाल से गोंद हटाकर ब्लाईटॉक्स–50 0.3 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए। इस दवा का छिड़काव पौधों पर भी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाग का उचित प्रबंधन भी रोग से बचाव करता है।

सूखा रोग (डाई बैक) – इस रोग में टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ सूख कर भूरी हो जाती है। पत्तियों पर भूरे बेंगनी धब्बे बनने से सूख कर गिर जाती है। इससे उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधा नष्ट हो जाता है। नियंत्रण के लिये रोगी भाग को काट कर अलग करें एवं मेन्कोजेब 2 ग्राम/लीटर पानी का घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त फरवरी व अप्रैल माह में सूक्ष्म तत्वों का पौधों पर छिड़कें।

झींगा पालन में तीव्र हेपेटोपैन्क्रिएटिक नेक्रोसिस रोग

● चोवतिया रविकुमार मनसुखभाई
● परमार बिंदिया कीर्तिकुमार
शोध छात्र, मात्स्यिकी महाविद्यालय, केरल मात्स्यिकी और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, केरल
● भावेश चौधरी
शोध छात्र, मात्स्यिकी महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (इम्फाल), लेम्बुचेर्रा, त्रिपुरा
bhaveshchoudhary@yahoo.com

वैश्विक अर्थव्यवस्था में जलीय कृषि उद्योग की एक बड़ी भूमिका है। यह व्यावसायिक क्षेत्रों को रोजगार के अवसर और राजस्व प्रदान करता है। इसकी मांग वर्षों से बढ़ती जा रही है और यह मानव उपभोग पर बहुत अधिक निर्भर है। जलीय कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में, क्रस्टेशियन उद्योग ने पिछले वर्षों में दुनिया भर में क्रस्टेशियन की बढ़ती बाजार मांग के कारण तेजी से विकास किया है। झींगा और झींगा उद्योगों को प्रमुख राजस्व उत्पादक माना गया है, और कई जलीय कृषक उपभोग के लिए प्राथमिक प्रोटीन स्रोतों के रूप में झींगा और झींगा की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाजार मूल्य के संदर्भ में व्यापार की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक झींगा माना जाता है। क्रस्टेशियन को दुनिया भर में उच्च मांग वाले आर्थिक रूप से प्रासंगिक जलीय कृषि उत्पादों के रूप में माना जाता है। 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियों से 2017 में कुल क्रस्टेशियन जलीय कृषि उत्पादन 8.4 एमटी था, जिसका मूल्य 61.06 बिलियन अमरीकी डॉलर था, 2000 के बाद से प्रति वर्ष 9.92 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ। समुद्री झींगा वर्तमान में क्रस्टेशियन एक्वाकल्चर पर 5.51 एम.टी. या कुल क्रस्टेशियन का 65.3 प्रतिशत (34.2 बिलियन अमरीकी डालर का मूल्य) के साथ हावी है, इसके बाद ताजे पानी की क्रस्टेशियन (2.53 एमटी या 29.9 प्रतिशत कुल क्रस्टेशियन) है और इसका मूल्य 24.3 बिलियन अमरीकी डालर है। यद्यपि झींगा वैश्विक जलीय कृषि उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, वे व्यापारिक समुद्री खाद्य उत्पादों के उत्पादन मूल्य का लगभग 16 प्रतिशत योगदान करते हैं। हालांकि, वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण, झींगा जलीय कृषि प्रणालियों की तीव्रता और विस्तार के दबाव ने अधिकांश जलीय कृषि व्यवसाय को नाजुक बना दिया है। वैश्विक कृषि में झींगा के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रमुख उत्पादक देशों, विशेष रूप से एशिया में, झींगा रोगों के कारण उत्पादन में गिरावट आई है।जलीय कृषि उद्योग में, एफ.ए.ओ. द्वारा बीमारी के प्रकोप से आर्थिक नुकसान प्रति वर्ष 9 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जो विश्व कृषि मछली और शेलफिश उत्पादन के मूल्य का लगभग 15 प्रतिशत है।

विशेष रूप से, जीवाणु रोगों ने पिछले दशकों के दौरान झींगा जलीय कृषि उद्योग में सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय अस्थिरता लाई है। विब्रियोसिस, एक महत्वपूर्ण जीवाणु रोग, अवसरवादी विब्रियो एसपीपी के कारण होता है। क्षेत्र में झींगा किसानों के लिए सबसे गंभीर खतरे के रूप में जारी है।जलीय कृषि में सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक जलीय जानवरों के स्वास्थ्य और उत्पादन को खतरे में डालने वाली विभिन्न बीमारियों की घटना है। समुद्री जानवर सचमुच संभावित रोगजनकों में तैरते हैं जो उन्हें वायरस, बैक्टीरिया, कवक और यहां तक कि प्रोटोजोआ के प्रति अतिसंवेदनशील बनाते हैं। वी. हार्वेई, वी. एल्गिनोलिटिकस, वी. एंगिलेरम, वी. स्प्लेन्डिडस, वी. सैल्मोनिसिडा, वी. वल्निफिकस और वी. पैराहेमोलिटिकस उपभेद वाइब्रियोसिस के मुख्य कारक जीवों के रूप में पाए गए हैं। कुछ विब्रियो स्पीशीज तीव्र हेपेटोपैन्क्रिएटिक नेक्रोसिस रोग (ए.एच.पी.एन.डी.) के लिए भी जिम्मेदार हैं जिसे मूल रूप से प्रारंभिक मृत्यु सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।

झींगा जलीय कृषि में एएचपीएनडी 2013 के अंत से बढ़ गया है, जब दक्षिण-एशियाई देशों में उद्योग ध्वस्त हो गया था। एएचपीएनडी, झींगा जलीय कृषि उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, तेजी से विकसित होता है, लगभग 8 दिनों के बाद स्टॉकिंग और गंभीर मृत्यु दर (100 प्रतिशत तक) 20-30 दिनों के भीतर होता है।

तीव्र हेपेटोपैन्क्रिएटिक नेक्रोसिस रोग (ए.एच.पी.एन.डी.) एक अपेक्षाकृत नई खेती की जाने वाली पेनेइड झींगा जीवाणु रोग है जिसे मूल रूप से प्रारंभिक मृत्यु दर सिंड्रोम (ई. एम. एस.) के रूप में जाना जाता है जो झींगा उद्योग में तबाही मचा रहा है। ए.एच.पी.एन.डी. का प्रकोप पहली बार 2009 में चीन में दिखाई देने के बाद से यह वियतनाम (2010) मलेशिया (2011) थाईलैंड (2012) मैक्सिको (2013) फिलीपींस (2015) और दक्षिण अमेरिका में फैल गया है। (2016) एएचपीएनडी झींगा की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है जिनमें वाणिज्यिक प्रजातियां, पी. मोनोडन, एल. वानामेई और एम. रोसेनबर्गी और क्रस्टेशियन मॉडल आर्टेमिया फ्रांसिस्काना शामिल हैं। इसके अलावा, झींगा के प्रारंभिक जीवन चरण, सामान्य रूप से, ए.एच.पी.एन.डी. संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

ए.एच.पी.एन.डी. की विशेषता झींगा हेपेटोपैंक्रियाज के गंभीर शोष के साथ-साथ रोग के तीव्र चरण में अद्वितीय हिस्टोपैथोलॉजिकल परिवर्तन हैं। इसके अलावा, जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, किसी भी रोगजनक की अनुपस्थिति में हेपेटोपैन्क्रिएटिक या पाचन तंत्र उपकला कोशिकाओं का बड़े पैमाने पर स्लोइंग झींगा पोस्ट-लार्वा स्टॉकिंग के लगभग पहले 30 दिनों के भीतर देखा जा सकता है। वास्तव में, ए.एच.पी.एन.डी. पैदा करने वाले बैक्टीरिया मुख्य रूप से पाचन ग्रंथि (हेपेटोपैंक्रियाज) को लक्षित करते हैं और हेपेटोपैन्क्रिएटिक आर (रिसॉर्पिटव) बी (फफोला) एफ (फाइब्रिलर) और ई (भ्रूण) कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप झींगा की शिथिलता और बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है।

ए.एच.पी.एन.डी. से प्रभावित झींगा सुस्ती, एनोरेक्सिया, धीमी वृद्धि, खाली पाचन तंत्र और पीला से सफेद हेपेटोपैंक्रियाज प्रदर्शित करता है। हालांकि, एएचपीएनडी के लिए ये रिपोर्ट किए गए नैदानिक संकेत कुछ अन्य बीमारियों के लिए आम हैं। उदाहरण के लिए, रासायनिक कारक, उदाहरण, नाइट्राइट और अमोनिया या माध्यमिक बैक्टीरिया (पारंपरिक विब्रियोसिस) और वायरल (व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, येलो हेड वायरस, आदि) द्वारा प्रेरित सकल संकेत। संक्रमण ए.एच.पी.एन.डी.विकृति का कारण भी बन सकता है। इसलिए, झींगा में ए.एच.पी.एन.डी. के पुष्टिकारक निदान के लिए सकल नैदानिक संकेतों के साथ बैक्टीरियल विषाणु कारक और ए.एच.पी.एन.डी.-विशिष्ट कोशिकीय परिवर्तनों की पहचान को सहायक माना जाता है।

ए.एच.पी.एन.डी.वी. पैराहेमोलिटिकस के कारक एजेंट के रूप में

विब्रियो पैराहेमोलिटिकस झींगा में ए.एच.पी.एन.डी. का कारण बनने वाली प्रमुख प्रजाति है। वी. पैराहाइमोलिटिकस विषमग्रामीय ग्राम-नकारात्मक, गैर-बीजाणु बनाने वाला और अल्पविराम के आकार का बैक्टीरिया है जिसमें ध्रुवीय फ्लैजेलम या कई फ्लैजेला होते हैं। यह रोगजनक ज्वारीय और तटीय वातावरण के ऑटोकथोनस माइक्रोफ्लोरा का हिस्सा है, साथ ही दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण क्षेत्रों में मछली, द्विभुज और क्रस्टेशियन का हिस्सा है। मछली और शेलफिश प्रजातियों (झींगा और मोलस्क सहित) के अलावा इस जीवाणु को पानी, तलछट, प्लैंकटन और समुद्री स्तनधारियों से अलग किया गया है।

पैराहेमोलिटिकस उच्च सोडियम क्लोराइड सांद्रता में पनप सकता है, 0.5 से 10 प्रतिशत तक 1 से 3 प्रतिशत के बीच इष्टतम स्तर के साथ, और मध्यम तापमान (5 से 37 °C) में बढ़ सकता है। झींगा जलीय कृषि में, वी. पैराहेमोलिटिकस एक महत्वपूर्ण जलीय रोगजनक है और कई उपभेद तीव्र हेपेटोपैन्क्रिएटिक नेक्रोसिस रोग (ए.एच.पी.एन.डी.) और अन्य महत्वपूर्ण बीमारी पैदा करने में सक्षम हैं जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है। ए.एच.पी.एन.डी. में संलिप्त वी. पैराहेमोलिटिकस उपभेद पी. वी. ए. 1 प्लास्मिड (70 के. बी.) ले जाने में अद्वितीय हैं जो विषाणु जीन, पी. आर. ए. वी. पी. और पी. आर. बी. वी. पी. को द्विआधारी पी. आर. ए. वी. पी./पी. आर. बी. वी. पी. विषाक्त पदार्थों को कूटबद्ध करते हैं।

ए.एच.पी.एन.डी. के सकल संकेत और हिस्टोपैथोलॉजी

प्राथमिक निदान विधि के रूप में, ए.एच.पी.एन.डी. के नैदानिक संकेतों का उपयोग प्रभावित झींगे की जांच के लिए किया जाता है। ए.एच.पी.एन.डी. से प्रभावित झींगे विशिष्ट रूप से एक पीला और सिकुड़ा हुआ हेपेटोपैंक्रियाज (एच. पी.) और गैस्ट्रिक और आंत खाली होना प्रदर्शित करते हैं। इसके व्यवहार में कुछ बदलाव जैसे सुस्ती, सर्पिल तैरना और कम भोजन भी देखा गया।

रोग के प्रारंभिक से मध्य चरण में एएचपीएनडी की मुख्य और अनूठी ऊतकीय विशेषताएँ हेपेटोपैन्क्रिएटिक ट्यूबुल एपिथेलियल कोशिकाओं का ढलना और बड़े पैमाने पर गोल होना है जिसमें कोई पता लगाने योग्य रोगजनक नहीं है।एएचपीएनडी के प्रारंभिक चरणों में, रोग की विशेषता बी (ब्लिस्टर लाइक) एफ (फाइब्रिलर) और आर (रिसॉर्पिटव) कोशिकाओं के मध्य से दूरस्थ शिथिलता, प्रमुख कैरिओमेगाली और ई कोशिकाओं में माइटोटिक गतिविधि की कमी है। जबरदस्त द्वितीयक संक्रमण द्वारा वर्णित अंतिम चरणों का मूल्यांकन करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, रोग के अंतिम चरणों में हीमोसाइट्स का विशाल एकत्रीकरण और मेलेनाइज्ड ग्रैनुलोमा का उद्भव होता है और ट्यूबुल लुमेन में विभिन्न बैक्टीरिया की कई कॉलोनियों के संक्रमण के साथ होता है। संक्रमित झींगे में इन अभिव्यक्तियों को विभिन्न जीवाणु प्रजातियों के गैर-एएचपीएनडी आइसोलेट्स द्वारा लाए गए गंभीर और अन्य पारंपरिक संक्रमणों से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है।

झींगा में ए.एच.पी.एन.डी. का निदान

झींगा में या कल्चर आवास में वी. पैराहेमोलिटिकस का जल्दी पता लगाने से ए.एच.पी.एन.डी. के प्रकोप को रोका जा सकता है। चूंकि विषाक्त पी. वी. ए. प्लास्मिड जो द्विआधारी पी. आर. ए. बी. विष को आश्रय देता है, पहली बार एक दशक पहले पहचाना गया था और इसकी विशेषता थी, इन दोनों विष जीन का उपयोग ए.एच.पी.एन.डी. निदान के लिए महत्वपूर्ण मार्कर के रूप में किया गया है। प्लास्मिड के साथ-साथ पी. आर. ए. बी. विष का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए विशिष्ट प्राइमर या जांच का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध अधिकांश ए.एच.पी.एन.डी. नैदानिक किट पी. सी. आर.-आधारित हैं और या तो पारंपरिक पी. सी. आर., नेस्टेड पी. सी. आर. या रियल-टाइम पी. सी. आर. तकनीकों का उपयोग करते हैं लेकिन इन किटों में समय लगता है और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। नैदानिक प्रयोगशालाओं के लिए, शोधकर्ताओं ने हाल ही में ए.एच.पी.एन.डी.का पता लगाने वाली प्रणालियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो उच्च-थ्रुपुट और बढ़ी हुई संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ कम समय लेने वाली हैं। उदाहरण के लिए, ए.एच.पी.एन.डी. का आसान, उच्च-थ्रूपुट पता लगाने के लिए पी. आर. ए., पी. आर. बी., झींगा 18 एस और बैक्टीरियल 16 एस जीन को लक्षित करने वाले प्राइमर का उपयोग करते हुए एक मल्टीप्लेक्स रियल-टाइम पी. सी. आर. विकसित किया गया है।

(क्रमशः)

'वीबी-जी राम जी' में

60 दिन कृषि के लिए, किसको होगा लाभ ?

● राजेश दुबे

कृषि में श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

हाल ही में समाप्त हुए वर्ष 2025 के अंतिम दिनों में केंद्र सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी विधेयक 'वीबी-जी राम जी' को विधिवत लागू करने सफलता पाई है। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल रही और इसके लाभ और नुकसान को लेकर केंद्र को विरोध और चिंताओं का सामना करना पड़ा, जो अभी भी जारी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर कुछ संशोधन के बाद लागू की जा रही इस योजना के समर्थन में केंद्र सरकार का एक दावा यह भी है कि इससे कृषि में श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कृषि के बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कोई काम नहीं किया जायेगा। जिसके कारण इस दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुगमता से हो सकेगी। इस तरह कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे श्रम संकट से निपटने में आसानी होगी। इन 60 दिनों में योजना के तहत कोई भी सार्वजानिक निर्माण कार्य नहीं होंगे।

श्रम की 60 दिनों की अवधि

राज्य सरकारें अपने कृषि जलवायु क्षेत्र, स्थानीय फसल चक्र और कृषि श्रम की आवश्यकता के अनुसार 60 दिनों की अवधि को अग्रिम रूप से अधिसूचित करेंगी। जो जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के अनुसार भिन्न भी हो सकती है। राज्य सरकार के अधिकारियों को कार्य योजना बनाने, मंजूरी देने और क्रियान्वयन के समय इस अधिसूचित अवधि को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा।

- 'मनरेगा' की जगह 'वीबी-जी राम जी'
- 100 की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी
- कृषि कार्यों के लिए 60 दिन योजना में काम बंद

कृषि श्रमिकों की आवश्यकता बनी रहती है

केंद्र सरकार ने केवल कुछ रिपोर्ट के आधार पर पूरे वर्ष में केवल 60 दिनों को ही कृषि कार्य की चरम परिस्थिति माना है जबकि सामान्य रूप से भी देखा जाये तो भारतीय कृषि में रबी और खरीफ दो मुख्य सीजन माने जाते हैं, अर्थात् चार बार तो बुआई और कटाई की ही परिस्थितियां बनती हैं। इसके अलावा भी कई कृषि कार्यों जैसे सिंचाई, निंदाई, खाद देने, दवाई देने आदि कार्यों के लिए भी कृषि श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय होगा कि आधुनिक कृषि में तो अब लगभग पूरे वर्ष फसल चक्र चलता रहता है, जिसके लिए निरंतर कृषि श्रमिकों की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे में 60 दिन की बंदिश की व्यवस्था योजना के समर्थन में केंद्र सरकार की जुमले बाजी ही लगती है। इसका दूसरा पहलू देखें तो कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के फलस्वरूप कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ही कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। जिसका लाभ लेते हुए किसान श्रमिकों पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इन श्रमिकों के लिए राहत का काम करती है। लेकिन 60 दिन की बंदिश एक ओर तो उन्हें राहत से वंचित करेगी वहीं कृषि की चरम परिस्थितियों में उनकी उचित श्रमिक दर को भी प्रभावित करेगी। इसका मतलब श्रमिकों के लिए 'एक तो दुबले,ऊपर से दो आषाढ़' जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी।

दो दशकों से चल रही मनरेगा योजना को कुछ नए प्रावधानों और नए नाम विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) के साथ प्रस्तुत करने का केंद्र सरकार यह दांव किसान, कृषि और श्रमिक में से किसके लिए कितना लाभकारी होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।

77वें गणतंत्र दिवस पर 'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' का संकल्प

मुख्यमंत्री ने दिया कृषि, सिंचाई और ऊर्जा विकास का रोडमैप

उज्जैन (कृषक जगत)। प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली।

वर्ष 2026 होगा 'किसान कल्याण वर्ष'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के आह्वान के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार चार मिशन-युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 27 हजार 50 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है।

10 बहुउद्देशीय गतिविधियां

किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्य फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। गौशालाओं के बजट को 250 करोड़ से बढ़ाकर 505 करोड़ रुपये किया गया है। प्रदेश की लगभग 3 हजार गौशालाएं पौने पांच लाख गौमाताओं की देखभाल कर रही हैं।

गेहूं, सोयाबीन और बोनस से किसानों को सीधा लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं उपार्जन किया गया और किसानों को 1360 करोड़ रुपये बोनस का भुगतान किया गया।

30 लाख विद्युत पम्प होंगे सोलर पम्प : मुख्यमंत्री ने कहा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन लगभग 10 घंटे बिजली मिल रही है। राज्य में 30 लाख विद्युत पम्पों को सोलर पम्प में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों की लागत घटेगी और सिंचाई सुलभ होगी।

सिंचाई विस्तार से बढ़ेगा उत्पादन

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते दो वर्षों में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। आने वाले समय में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लक्ष्य है।

2 सिंचाई परियोजनाओं से 8000 हेक्टेयर से अधिक में होगी सिंचाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में नर्मदापुरम जिले में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ 47 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार तवा परियोजना (दायीं तट नहर) की बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना की लागत 86 करोड़ 76 लाख रूपये, प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 4200 हेक्टेयर की स्वीकृति प्रदान की गयी। परियोजना से नर्मदापुरम जिले की बाबई एवं सोहागपुर तहसील के 33 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। तवा परियोजना की दांयी तट नहर से पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना की लागत 128 करोड़ 71 लाख रूपये, प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 6000 हेक्टेयर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना से नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर तहसील के 30 ग्राम लाभान्वित होंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया

वर्ष 2024-25 में 357 मिलियन टन से अधिक पहुँचा उत्पादन : श्री चौहान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि देश कृषि और ग्रामीण विकास- दोनों मोर्चों पर अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है।

कृषि क्षेत्र में निरंतर और स्थिर प्रगति

श्री चौहान ने कहा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में औसत वार्षिक विकास दर स्थिर मूल्यों पर 4.4 प्रतिशत रही है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2016 से 2025 के दौरान कृषि क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर 4.45 प्रतिशत रही है, जो पिछले दशकों की तुलना में सर्वाधिक है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भी कृषि क्षेत्र ने 3.5 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है, जो इस क्षेत्र की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश का खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज (श्री अन्न) की बेहतर पैदावार के कारण संभव हुई है।

बागवानी क्षेत्र बना कृषि विकास का उज्ज्वल पक्ष

श्री चौहान ने कहा कि कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बागवानी क्षेत्र सबसे उज्ज्वल पक्ष के रूप में उभरा है। बागवानी उत्पादन वित्तीय वर्ष 2013-14 में 280.70 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 367.72 मिलियन टन तक पहुँच गया है।

इस दौरान फलों का उत्पादन 114.51 मिलियन टन, सब्जियों का 219.67 मिलियन टन तथा अन्य बागवानी फसलों का उत्पादन 33.54 मिलियन टन रहा।

महाराष्ट्र में 2696 करोड़ की अरहर खरीदी को मंजूरी

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बैठक कर महाराष्ट्र में अरहर की 3.37 लाख मीट्रिक टन खरीद, जिसकी एमएसपी राशि लगभग 2696 करोड़ रुपए है, को मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के तहत स्वीकृति दे दी है। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने राज्य के विपणन (मार्केटिंग) मंत्री श्री जयकुमार रावल के साथ खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने नेफेड, एनसीसीएफ और राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि खरीद सही तरीके से हो। किसानों से सीधी खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ वास्तविक किसान तक पहुंच पाएगा।

फोटो गैलरी

म.प्र. की झांकी

नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में देवी अहिल्याबाई पर केन्द्रित मध्य प्रदेश की आकर्षक झांकी आकर्षण का केन्द्र बनी।

आनंद ही आनंद

उज्जैन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सपत्नीक आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

स्वागत

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 'समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र गणतंत्र दिवस अभिनंदन समारोह 2026' कार्यक्रम में देश भर से आई लखपति दीदियों, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) दीदियों का स्वागत किया।

डायरी भेंट

भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा को कृषक जगत डायरी 2026 भेंट करते हुए श्रवण मीणा।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

रबी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

किसान कृषि यंत्रीकरण को अपनायें : श्री शर्मा

बालाघाट

बालाघाट (कृषक जगत)। कृषि विज्ञान केंद्र, बड़गांव में गत दिनों रबी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. टी.आर. शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने की। वे गूगल मीट के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. रजनीश श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अटारी जोन-9 जबलपुर तथा डॉ. प्रमोद गुप्ता, वैज्ञानिक, ज.ने.कृ.वि. वि., जबलपुर भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषक एवं महिला कृषक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत में कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एस.आर. धुवारे ने खरीफ 2025 के दौरान केंद्र द्वारा संपादित कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की तथा रबी 2025-26 में प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी दी। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. टी.आर. शर्मा ने कहा कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को देखते हुए किसानों को कृषि यंत्रीकरण को अपनाना चाहिए। उन्होंने जिले में सोयाबीन एवं रामतिल पर प्रक्षेत्रीय परीक्षण, प्राकृतिक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। वरिष्ठ वैज्ञानिक अटारी जोन-9 जबलपुर डॉ. रजनीश श्रीवास्तव ने ड्रैगन फ्रूट एवं सिंघाड़ा जैसी लाभकारी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने, कद्दूवर्गीय सब्जियों की पौध तैयार कर किसानों को वितरित करने तथा पारंपरिक किस्मों के संरक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। कृषि महाविद्यालय बालाघाट के अधिष्ठाता डॉ. घनश्याम देशमुख ने खरीफ में अपलैण्ड भूमि पर उठी हुई क्यारियों में अरहर उत्पादन तथा राइस ट्रांसप्लांटर, सुपर सीडर एवं लेजर लेवलर जैसे कृषि यंत्रों के उपयोग पर जोर दिया।

उप संचालक कृषि बालाघाट श्री फूल सिंह मालवीय ने किसानों को सलाह दी कि नया बीज खरीदने के बाद उसका उपयोग कम से कम तीन वर्षों तक किया जाए। साथ ही अपलैण्ड भूमि पर सोयाबीन एवं रामतिल जैसी फसलों को अपनाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार मौसम वैज्ञानिक श्री धर्मेन्द्र आगाशे ने किया।

सोलर पम्प लगाने के जिला समिति की बैठक हुई

छिंदवाड़ा (कृषक जगत)। कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' (कुसुम-ब) के अंतर्गत सोलर पम्प स्थापना के संबंध में जिला स्तरीय समिति की

छिंदवाड़ा

बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर श्री धीरेन्द्र सिंह, उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह, अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल श्री सुनील कुमार सिंहा एवं नवीकरणीय ऊर्जा अधिकारी सुश्री शालू पासी और वेंडर सहित जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री नारायन ने नवीकरणीय ऊर्जा आधिकारी, लीड बैंक मैनेजर, अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल और सभी जनपद सीईओ को किसानों को योजना का लाभ दिलाने और समुचित मार्गदर्शन देने के लिए बेहतर आपसी समन्वय द्वारा विकासखंड स्तर पर शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा अधिकारी सुश्री पासी ने बताया कि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के लिए छिन्दवाड़ा जिले के 475 कृषकों को लाभान्वित किया जाना है। उनके द्वारा योजना के तहत 10 प्रतिशत की राशि जमा कर दी गई है, शेष प्रक्रियाओं में उनके सहयोग के लिए विकासखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।

प्रदेश में कृषकों की भूमि पर सोलर पंप की स्थापना के लिये, वर्तमान में ''प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना'' के अंतर्गत किसानों को 1 एच.पी. से 7.5 एच.पी. तक क्षमता के पम्पा पर 90 प्रतिशत सब्सिडी (अनुदान) दिये जाने का प्रावधान है। सोलर पंप की दैनिक उपयोगिता उपरांत, सोलर पैनलों की उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा के वैकल्पिक उपयोग के लिए यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर (यू.एस.पी.सी.) के उपयोग का विकल्प भी कृषकों को दिया गया है।

अखिलेश ने उद्यानिकी फसलों को अपनाया

अधिक मुनाफा कमाया

बैतूल (कृषक जगत)। चिचोली तहसील के ग्राम निवारी निवासी प्रगतिशील किसान श्री अखिलेश सोनी ने पारंपरिक खेती से हटकर उद्यानिकी फसलों को अपनाया और कम समय में अधिक मुनाफा कमाकर क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। किसान श्री सोनी ने उद्यानिकी विभाग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत ड्रिप सिस्टम स्थापित किया। इसके बाद

बैतूल

उन्होंने 1.40 एकड़ क्षेत्र में अभिलाष किस्म के टमाटर की खेती की, जिससे मात्र 110 दिनों में 1 लाख रुपए की लागत पर 2.75 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। खास बात यह है कि उनके खेत में अभी भी करीब 3 से 4 लाख रुपए मूल्य के टमाटर लगे हुए हैं।

बड़ी मंडियों में करेंगे बिक्री - किसान अखिलेश ने बताया कि वर्तमान में खेत में लगे टमाटर जैसे-जैसे तैयार होंगे, उन्हें भोपाल, नागपुर और अमरावती की बड़ी मंडियों में बेचा जाएगा। इन बाजारों में बेहतर भाव मिलने से आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई पीएमडीसी योजना के अंतर्गत 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिस्टम का लाभ लिया, जिसकी इकाई लागत 1.27 लाख आई और कृषक को 0.54 लाख का अनुदान मिला।

सब्जी, फूलों से हो रही अतिरिक्त आय- किसान ने बताया कि टमाटर के साथ-साथ धनिया, पालक, पत्ता गोभी, मेथी, भटे और गेंदे के फूलों की खेती भी कर रहे हैं। विविध फसलें लेने से उन्हें सालभर नियमित आय मिल रही है।

डिंडोरी

मत्स्य पालन में प्रेमवती को मिला सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार

डिंडोरी (कृषक जगत)। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम किंवटी की निवासी श्रीमती प्रेमवती अमान सिंह ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर जिले को राज्य स्तर पर गौरवान्वित किया है। आत्मा परियोजना (आत्मा) अंतर्गत वर्ष 2023-24 के मूल्यांकन में उन्हें राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार (श्रेणी-मत्स्य विभाग) से सम्मानित किया गया है। इसके तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा उन्हें 25,000/- की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

श्रीमती प्रेमवती अमान सिंह को मत्स्य विभाग की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालाब निर्माण एवं आवश्यक इनपुट्स हेतु कुल 4.40 लाख की स्वीकृति दी गई, जिसमें 2.64 लाख (60 प्रतिशत) अनुदान शामिल था। इस सहायता से उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन की शुरुआत की। उन्होंने मत्स्यबीज स्पान संवर्धन किया तथा पंगेसियस, रोहु, कतला और मृगल प्रजातियों का पालन कर 2.50 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया। इससे उन्हें लगभग 3.40 लाख की शुद्ध आय प्राप्त हुई, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

मोनू ने सोशल मीडिया से की मशरूम खेती की शुरुआत

सागर (कृषक जगत)। सागर जिले के रहली ब्लाक के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले श्री मोनू तिवारी ने अपने साथी सोनू के साथ मिलकर मशरूम की खेती अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का छोटा सा प्रयास किया है। इन युवाओं ने मशरूम उत्पादन को आजीविका का साधन बनाकर न केवल आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं।

सागर

मोनू ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखकर मशरूम की खेती करना सीखा है। उन्होंने अपने छोटे से कमरे में मशरूम की खेती का पहला प्रयोग किया है, और पहली फसल को दमोह, जबलपुर, सागर एवं स्थानीय सब्जी मंडी में बेचने के लिए सैंपल भेजे हैं। 'मैंने बिना ट्रेनिंग घर पर रहकर ही सोशल मीडिया पर देखकर मशरूम की खेती करना सीखा है। यह छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इससे कम लागत में अच्छी आमदनी कर सकते हैं और परिवार के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकते हैं।'

मोनू ने बताया कि 30-40 दिनों में फसल तैयार हो जाती है। इसकी फुटकर बिक्री 350 से 400 रुपये प्रति किलो है, जबकि थोक में 150 से 200 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। अब तक 10 किलो मशरूम निकाली गई है, जिसे जबलपुर, दमोह, सागर और स्थानीय मंडी में सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। मोनू ने कहा, 'इस खेती की देखरेख बहुत कठिन है, खासकर गर्मियों में तापमान को 25 डिग्री पर रखना पड़ता है। लागत लगभग 80 से 90 रुपये प्रति किलो आती है, लेकिन अच्छी आमदनी की उम्मीद है।'

समस्या -समाधान

समस्या– गेहूं की पत्तियों पर काला–काला चूर्ण दिखाई दे रहा है। तनों पर भी इसी प्रकार का आक्रमण है कौनसा रोग है, क्या उपाय है।

– विक्रम सिंह

समाधान– *आपके क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दूरभाष पर चर्चा होने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि गेहूं की पत्तियों पर कंडुआ रोग आया है इसे लोग गेहूं का काला गेरूआ मान रहे थे परंतु काले गेरूए के लक्षण के विपरीत पत्तियों पर काली चूर्ण पत्तियों का कंडुआ ही है। जो एक अर्से के बाद खेतों में दिखाई दिया उसके पौधे रोग के फैलाव के लिये उपयुक्त तापमान एवं आर्द्रता है। गेहूं की बीमारी बंट और पत्तियों का कंडुआ ऐसी बीमारी है जिसकी कवक बीज और भूमि चालित होती है। अर्थात् बीज के द्वारा खेतों में आकर भूमि में लुकी–छिपी रहती है। और वातावरण उपयुक्त होते ही प्रदर्शित हो जाती है। पत्तियों पर छिड़काव से लाभ नहीं होगा आने वाले वर्षों में ये करें–*

- *बीज पूरी तरह बदल दें साथ ही फसल का फेरबदल जरूर करें।*
- *बीज का उपचार वीटावैक्स 2 ग्राम दवा/किलो बीज का करें।*

समस्या– मैंने दो एकड़ में मसूर लगाई थी कटाई के लिये तैयार होने वाली है, इसे काटकर क्या मूंग लगाया जा सकता है। विस्तार से बतायें।

– माखनलाल मौर्य

समाधान– *आपकी मसूर कटने वाली है आपके पास पानी की सुविधा है इसलिये आप सरलता से मूंग लगा सकते हैं और मूंग उत्पादन की तकनीकी का विस्तार से प्रकाशन किया जा चुका है। आप हमारे सदस्य हैं कृपया उक्त लेख को पढ़कर अतिरिक्त जानकारी अवश्य प्राप्त करें। फिलहाल तकनीकी के प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख निम्नानुसार है।*

- *प्रमुख जातियों में के 851, पी.एस.16, पी.एस. 7, पूसा वैशाखी।*
- *बीज का उपचार 3 ग्राम थाईरम प्रति किलो बीज का करे।*
- *40 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे.*
- *फूल आने से पहले और दाना भरते समय सिंचाई आवश्यक है 75 प्रतिशत फल्लियां बन जाने के बाद सिंचाई नहीं करें। पहली सिंचाई बुआई के 15 दिनों बाद करें।*

समस्या– चने की घेटी आने लगी है कहीं–कहीं इल्ली का प्रकोप देखा है। उपाय बतायें।

– अमरनाथ वर्मा

समाधान– *आपने चने की बुआई में देरी कर दी होगी। घेटी की अवस्था में इल्ली के आक्रमण से नुकसान संभव है आप शीघ्र ही निम्न उपचार करें।*

- *कीटनाशी क्विनालफास 25 ई.सी. जो एक संपर्क एवं दैहिक कीटनाशक है। 1 ली./500 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर से दो छिड़काव करें।*
- *अथवा प्रोफेनोफॉस 50 ई.सी. कीटनाशक जो अंड संपर्क एवं उदरनाशी है की 1.5 लीटर मात्रा 500–600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतर से दो छिड़काव करें।*
- *यदि खेत में T आकार की खूटियां नहीं लगाई हो तो तुरंत लगाये ताकि इल्ली के जीवनचक्र में बाधा पहुंच सकें।*

समस्या– चूहों को मारने की दवा एवं कल्चरल उपाय बतायें।

– छोटे लाल राय, कुठुलिया

समाधान– *चूहा और दीमक दोनों सामाजिक त्रासदी है। जिनका असर खेती तथा घरों तक होता है। चूहा एक बहुत ही चालाक और सतर्क प्राणी होता है। उसको नियंत्रण में रखने के लिये छल/प्रपंच करना होता है।*

- *खेत में जगह–जगह घूम कर चूहों के सक्रिय बिलों का सर्वेक्षण करें।*
- *फूले चने, मुरमुरे इत्यादि को रोज बिल के आसपास दो दिनों तक डालकर चूहों के लिये आकर्षण पैदा करें ।*
- *अच्छा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ देने के बाद 4 दिन बाद जिंक फास्फेट 2.5 ग्राम को 100 ग्राम आटे में मिलायें। उसमें तेल तथा गुड़ भी डालें। स्वादिष्ट गोलियों को सक्रिय बिलों के पास रखें।*
- *खेत में जगह–जगह खूटे गाड़ें ताकि उस पर रात में उल्लू बैठ सकें और चूहों को उठा सकें।*

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

प्राकृतिक खेती - अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रिसोर्स और सपोर्ट

मुझे भारत में प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण और शिक्षण संसाधन कहाँ मिल सकते हैं?

लोकल कृषि विस्तार सेवा, सरकारी प्रोग्राम, एनजीओ, और प्राकृतिक खेती पर केन्द्रित करने वाले ऑनलाइन कोर्स और फोरम से ट्रेनिंग लें।

क्या कोई सरकारी पहल या प्रोग्राम हैं जो प्राकृतिक खेती को सपोर्ट करते हैं?

हाँ, परंपरागत कृषि विकास योजना (RKVY) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) जैसी सरकारी पहल प्राकृतिक खेती के तरीकों के लिए सपोर्ट देती हैं।

क्या मैं सहायता और नेटवर्किंग के लिए किसी स्थानीय प्राकृतिक खेती को-ऑपरेटिव या एसोसिएशन से जुड़ सकता हूँ?

हाँ, लोकल को-ऑपरेटिव या एसोसिएशन से जुड़ने से कीमती सहयोग, ज्ञान साझा और आदानों तक पहुँच मिल सकती है।

प्राकृतिक खेती करने वाले भारतीय किसानों के लिए कौन से ऑनलाइन फोरम या कम्युनिटी उपलब्ध हैं?

सोशल मीडिया ग्रुप, फोरम और प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित वेबसाइट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मार्गदर्शन और सहयोग के लिए एक जैसी सोच वाले किसानों और एक्सपर्ट से जोड़ सकते हैं।

बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या है?

जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का मतलब है किसी इकोसिस्टम में रहने वाले पौधों, जानवरों और दूसरे जीवों की संख्या और वैरायटी।

किसानों के लिए बायोडायवर्सिटी की समझ क्यों ज़रूरी है?

बायोडायवर्सिटी किसानों को यह समझने में मदद करती है कि इकोसिस्टम में अलग-अलग स्पीशीज़ एक-दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि हम अपनी ज़मीन को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी फ़ूड सप्लाई को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ा सकें।

प्राकृतिक फ़ार्मिंग बायोडायवर्सिटी बनाए रखने में कैसे मदद करती है?

प्राकृतिक फ़ार्मिंग में नुकसानदायक केमिकल फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता, और यह मिट्टी में जैविक मैटर बढ़ाने पर केन्द्रित रहती है। स्वस्थ मिट्टी फ़ायदेमंद माइक्रोब्स, केंचुओं वगैरह जैसी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी को सहयोग करती है। यह फ़ायदेमंद कीड़ों/पक्षियों/परागण की आबादी बनाए रखने में मदद करती है।

कृषक जगत

बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक	सब्जियों में पौध संरक्षण	मशरूम एक लाभ अनेक	मिर्च की उन्नत खेती	केला उत्पादन	गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण
रु. 95	रु. 75	रु. 45	रु. 55	रु. 70	रु. 75
कोड : 016	कोड : 017	कोड : 019	कोड : 020	कोड : 025	कोड : 027

पपीता	अदरक	फलों की खेती	सजाएं फूलों से बगिया	घर की बगिया
रु. 55	रु. 55	रु. 75	रु. 65	रु. 95
कोड : 031	कोड : 032	कोड : 040	कोड : 041	कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____

ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____

जिला _____ फोन/मोबा. _____

कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____

संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी आर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य

फल जो हैं स्वास्थ्यवर्द्धक

फल एक ऐसा हेल्दी स्नैक है जिसे कभी भी खाया जा सकता है। प्रतिदिन फल खाने से कई बीमारियों के होने की आशंका कम होती है। फल तो सब खाते हैं पर कौन सा फल फायदेमंद होता है हममें से कितने जानते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो जानिए कुछ फलों के बारे में खास बातें।

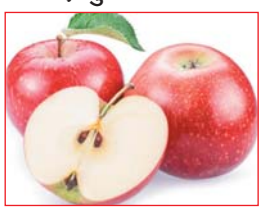

सेब

डॉक्टरों का मानना है कि एक सेब प्रतिदिन खाने से कई एक फायदे मिलते हैं। सेब विटामिन ए व सी से भरपूर फल है। इसमें कार्बोहाइड्रेड व सेल्यूलोज भी होता है। इसलिए सेब के सेवन से अल्परक्तता, तेज बुखार, कमजोरी, निराशा, आर्थराइटिस, मुंहासे व रक्त की अशुद्धियां जैसी समस्याएं दूर होती हैं तथा क्षीण जीवनशक्ति के उपचार में मदद मिलती है।

आम

फलों का राजा कहा जाने वाला आम आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर से भरपूर आम मल त्याग और चयापचय दर को बढ़ाने में मदद करता है।

तरबूज

तरबूज आकर्षक और स्वास्थ्य वर्द्धक फल है। तरबूज खाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। हमें वही फल ज्यादा खाने चाहिए जो शरीर में पानी की आपूर्ति भी करते रहें। तरबूज रक्ताचाप को संतुलित रखता है और कई बीमारियां दूर करता है। इसके और भी फायदे हैं जैसे खाना खाने के उपरांत तरबूज का रस पीने से भोजन शीघ्र पच जाता है। मोटापा कम करने वालों के लिए यह उत्तम आहार है।

संतरा

संतरा विटामिन सी से परिपूर्ण होता है, जिससे हमारे शरीर का प्रतिरक्षातंत्र मजबूत बनता है और बाहर से आने वाली बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। सर्दी, जुकाम, खांसी होने पर संतरे का सेवन लाभप्रद होता है।

अनार

अनार पतले पारदर्शी लाल रंग के रसीले दानों का फल है। इसमें साइट्रिक अम्ल के साथ विटामिन बी व सी होता है। अनार में एंटी आक्सीडेंट विशेषता होने के कारण यह खराब कोलेस्ट्रॉल को शुरुआती अवस्था में ही रोक देता है। अनार का जूस खून को पतला बनाने की विशेषता भी रखता है जिससे खून के थक्के नहीं बनते।

चीकू

चीकू एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। चीकू के फल में 71 प्रतिशत पानी, 1.5 प्रतिशत प्रोटीन, 1.5 प्रतिशत चर्बी और साढ़े पच्चीस प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमे विटामिन ए तथा विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है।

पपीता

पपीता सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जहां इससे पेट संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, वहीं त्वचा भी काफी अच्छी हो जाती है। जिन लोगों को किडनी की तकलीफ होती है उन्हें रोज पपीता खाना चाहिए। पपीता खाने से आंखों की रोशनी भी अच्छी बनी रहती है। अगर पेट में कीड़े हों, तो कच्चे पपीते का जूस फायदा करता है।

कैसे लगाएं पारिवारिक सदस्यों के फोटो

- तीन व्यक्तियों की एक सीध में एकाकी फोटो हो तो घर में न रखें।
- फोटो कभी भी टांगें नहीं।
- अगर दीवार पर फोटो लगानी हो तो उसके नीचे एक लकड़ी की पट्टी लगाएं अर्थात् वह फोटो लकड़ी के पट्टे पर टिके।
- फोटो का मुख बाथरूम की ओर न हो।
- प्रमुख द्वार की ओर कदापि न हो।
- सीढ़ियों की ओर न दिखे।
- तलघर में कभी भी परिवार के सदस्यों की अथवा ईश्वर की फोटो न लगाएं।

खेल, नृत्य और तैरना फायदेमंद

फिटनेस के लिए फुटबॉल और वॉलीबॉल के दो गेम पर्याप्त हैं। दोनों खेलों के लिए पूरी टीम हो, जरूरी नहीं है। शौक के तौर पर आधी टीम से भी इन्हें खेला जा सकता है। बैडमिंटन भी एक जबरदस्त कसरत है। इसके अलावा डांसिंग यानी एरोबिक्स भी एक तरह की कसरत ही है। इससे दिल और फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। साथ ही शारीरिक संतुलन भी सुधर जाता है। आप जितनी मर्जी हो, उतने समय तक डांस कर सकते हैं।

कहा जाता है कि तैरने और घुड़सवारी से बड़ी कोई कसरत नहीं होती, जिसमें शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। तैराकी शुरू करने में उतना भी खर्च नहीं करना पड़ता, जितना दौड़ने के जूते खरीदने में हो सकता है। दरअसल तैराकी के लिए आपको सिर्फ एक बढ़िया स्वीमिंग–कॉस्ट्यूम की जरूरत होती है।

यदि आप किसी नदी या तालाब में तैराकी करते हैं तो इससे अच्छा विकल्प नहीं है।

स्वास्थ्य/शिक्षण

डायबिटीज के लिए सरल देशी नुस्खे

डायबिटीज अब उम्र, देश व परिस्थिति की सीमाओं को लांघ चुका है। इसके मरीजों का तेजी से बढ़ता आंकड़ा दुनियाभर में चिंता का विषय बन चुका है। जानते हैं कुछ देशी नुस्खे मधुमेह रोगियों के लिए–

नीबू

मधुमेह के मरीज को प्यास अधिक लगती है। अतः बार–बार प्यास लगने की अवस्था में नीबू निचोड़कर पीने से प्यास की अधिकता शांत होती है।

खीरा

मधुमेह के मरीजों को भूख से थोड़ा कम तथा हल्का भोजन लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बार–बार भूख महसूस होती है। इस स्थिति में खीरा खाकर भूख मिटाना चाहिए।

गाजर–पालक

इन रोगियों को गाजर–पालक का रस मिलाकर पीना चाहिए। इससे आंखों की कमजोरी दूर होती है।

शलजम

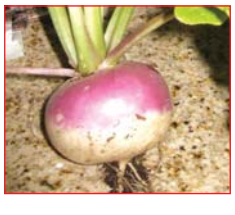

मधुमेह के रोगी को तरोई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। शलजम के प्रयोग से भी रक्त में स्थित शर्करा की मात्रा कम होने लगती है। अतः शलजम की सब्जी, पराठे, सलाद आदि चीजें स्वाद बदल–बदलकर ले सकते हैं।

जामुन

मधुमेह के उपचार में जामुन एक औषधि है। जामुन की गुठली, छाल, रस और गूदा सभी मधुमेह में बेहद फायदेमंद हैं। जामुन के बीजों में जाम्बोलिन नामक तत्व पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदलने से रोकता है। गुठली का बारीक चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिए। दिन में दो–तीन बार, तीन ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से मूत्र में शुगर कम होती है।

करेले

प्राचीन काल से करेले को मधुमेह की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका कड़वा रस शुगर की मात्रा कम करता है। मधुमेह के रोगी को इसका रस रोज पीना चाहिए। इससे आश्चर्यजनक लाभ मिलता है।

मैथी

मधुमेह के उपचार के लिए मैथीदाने के प्रयोग का भी बहुत चर्चा है। दवा कंपनियां मैथी के पावडर को बाजार तक ले आई हैं। इससे पुराना मधुमेह भी ठीक हो जाता है। मैथीदानों का चूर्ण बनाकर रख लीजिए। नित्य प्रातः खाली पेट दो टी–स्पून चूर्ण पानी के साथ निगल लीजिए। कुछ दिनों में आप इसकी अद्‌भुत क्षमता देखकर चकित रह जाएंगे।

गेहूं के जवारे

गेहूं के पौधों में रोगनाशक गुण विद्यमान हैं। गेहूं के छोटे–छोटे पौधों का रस असाध्य बीमारियों को भी जड़ से मिटा डालता है। इसका रस मनुष्य के रक्त से चालीस फीसदी मेल खाता है। इसे ग्रीन ब्लड के नाम से पुकारा जाता है। जवारे का ताजा रस निकालकर आधा कप रोगी को तत्काल पिला दीजिए।

पाक्षिक पंचांग

2 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक
विक्रम संवत् 2082
फाल्गुन कृष्ण 1 से फाल्गुन कृष्ण 13 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
2	फरवरी	सोम	फाल्गुन कृष्ण	1
3	फरवरी	मंगल	----------	2
4	फरवरी	बुध	----------	3
5	फरवरी	गुरु	----------	4 गणेश चतुर्थी व्रत
6	फरवरी	शुक्र	----------	5
7	फरवरी	शनि	----------	6
8	फरवरी	रवि	----------	7
9	फरवरी	सोम	----------	8
10	फरवरी	मंगल	----------	8
11	फरवरी	बुध	----------	9
12	फरवरी	गुरु	----------	10
13	फरवरी	शुक्र	----------	11 विजया एकादशी
14	फरवरी	शनि	----------	12 प्रदोष व्रत
15	फरवरी	रवि	----------	13 महाशिवरात्रि

गणतंत्र दिवस की चित्रमय झलकियां

भोपाल

भोपाल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित झांकी को प्रथम स्थान मिला। कृषि विभाग जिला भोपाल एवं मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार झांकी की थीम भावांतर भुगतान योजना एवं विजन 2047 पर आधारित थी। लोकरंग कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पुरस्कार लेते उप संचालक कृषि श्रीमती सुमन प्रसाद एवं मंडी बोर्ड के श्री योगेश नागले।

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह में कृषि विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान मिला। जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह से पुरस्कार लेते उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह। इस अवसर पर कलेक्टर श्री हरेन्द्र नारायण एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

मसाला फसलों के मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण

नीमच (कृषक जगत)। कृषि विज्ञान केन्द्र, नीमच में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के अटारी जोन-9 जबलपुर द्वारा निर्देशित एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर द्वारा संचालित आर्या योजनान्तर्गत ग्रामीण नवयुवकों एवं कृषकों हेतु मसाला फसलों के मूल्य संवर्धन पर सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नीमच, मनासा और जावद तीनों विकासखण्डों के नवयुवक, युवतियों एवं किसानों ने प्रशिक्षण का लाभ लिया।

कार्यक्रम में केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. सी. पी. पचौरी ने मसाला फसलों की उत्पादन तकनीकी बताते हुए उनकी उन्नत प्रजातियों, खाद एवं उर्वरक की जानकारी दी। केन्द्र की वैज्ञानिका डॉ. शिल्पी वर्मा ने मसाला फसलों के मूल्य संवर्धन

नीमच

के विभिन्न आयाम पर विस्तृत रुप से व्याख्यान दिए।

तकनीकी सत्र में केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. पी. एस. नरूका, डॉ. एस. एस. सारंगदेवोत वरिष्ठ वैज्ञानिक पौध संरक्षण, डॉ. जे. पी. सिंह सस्य वैज्ञानिक के व्याख्यान हुए। प्रशिक्षण में उपसंचालक, उद्यानिकी श्री अंतरसिंह कन्नोजे, लीड बैंक नीमच के महाप्रबंधक श्री शितान्सु शेखर एवं डी.आर.पी. कन्सलटेंट श्री सुभाष शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी ओ. एस. बर्मन कृषि द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग धंधों से संबंधित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं सब्सिडियों एवं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बारे में विस्तार से बताया।

कृषकों को बताये गुलाबी इल्ली से बचाव के तरीके

आईआरएम परियोजना के तहत कृषक प्रशिक्षण

खंडवा

खण्डवा (कृषक जगत)। बीएम कृषि महाविद्यालय खण्डवा में केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर के सहयोग से कपास में ''कीटनाशक प्रतिरोधकता प्रबंधन'' के अंतर्गत कपास उगाने वाले कृषकों को कपास में लगने वाले कीटों एवं उनके नियंत्रण एवं बचाव हेतु गैर रासायनिक विधियों से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें गुलाबी इल्ली जो पिछले कई वर्षों से कपास उत्पादक किसानों को बहुत परेशान कर रही है। कृषक इसके बचाव हेतु रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो पर्यावरण एवं मनुष्य के लिये अत्यंत ही हानिकारक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के अधिष्ठाता, डॉ. डी. एच. रानडे ने किसानों को बताया कि वो वैज्ञानिकों के द्वारा बताये गये उपायों को अपनाकर कीटनाशकों के प्रयोग में कमी ला सकते हैं।

डॉ. प्रद्युम्न सिंह, वैज्ञानिक कीटशास्त्र ने बताया कि कृषि महाविद्यालय के प्रक्षेत्र पर गैर रासायनिक विधियों द्वारा कीटों का नियंत्रण किया जा रहा है।

इसी परियोजना के अंतर्गत परियोजना को लाभार्थी कृषकों के प्रक्षेत्र पर परियोजना प्रभारी डॉ. प्रद्युम्न सिंह, वैज्ञानिक कीटशास्त्र के द्वारा जिसके लिये उन्होंने कृषकों को गुलाबी इल्ली वाला ल्यूर (केप्सूल) के साथ फेरोमोन प्रपंच का उपयोग एवं फेरोमोन क्रीम के उपयोग करने की सलाह दी।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. एम. के. तिवारी, सहायक प्राध्यापक एवं आभार श्री मंगेश सोनी एवं श्री शुभम पटेल ने किया।

धान खरीदी में लापरवाही पर केंद्र प्रभारियों को हटाया

कटनी (कृषक जगत)। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन केंद्रों में लापरवाही बरतने वाले उपार्जन केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्टरर श्री आशीष तिवारी के सख्त निर्देश और कड़े रूख की वजह से उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता पाये जाने पर चार उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को आगामी दो वर्षों के लिए उपार्जन कार्य से पृथक कर दिया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सज्जन सिंह परिहार ने बताया कि कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा गठित अधिकारियों के संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र कौड़िया, हथियागढ़, निगहरा एवं विजयराघवगढ़ में दस्तावेजों का संधारण नियमानुसार नहीं किया जाना, धान की बोरियों में स्टेंसिल और टैग का न होना और तौल कार्य में खामियां पाई गई। जिसके बाद चारों उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था।

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
➪ वार्षिक रु. 600/-
➪ दो वर्ष रु. 1000/-
➪ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से 'कृषक जगत' - प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793,
Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत
भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

छिंदवाड़ा सीईओ ने एफपीसी का किया औचक निरीक्षण

छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा (कृषक जगत)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार ने गत दिवस एसआरएलएम सतपुड़ा किसान उत्पादक कंपनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंपनी के व्यवसायिक मॉडल की समीक्षा की और कंपनी की समग्र प्रगति के सुधार के लिए बहुमूल्य सुझाव प्रदान किया। उन्होंने एसआरएलएम की टीम के सहयोग से छिंदवाड़ा में कार्यरत समस्त उत्पादक समूहों को सतपुड़ा उत्पादक कंपनी में जोड़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि इस पहल से उत्पादक कंपनी का विस्तार करने में सहयोग होगा। सतपुड़ा मृदा लैब, सतपुड़ा श्री अन्न खरीदी पर भी चर्चा की गई। सुनारी मोहगांव में कृष्णा प्रोड्यूसर ग्रुप की दीदियों से चर्चा की गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुमार द्वारा जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत भाजीपानी में एक बगिया मां के नाम तहत लगाए गए आम के पौधों का भी औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कुमार द्वारा ग्राम डागावानी पिपरिया में महुआ कुकीज यूनिट का उद्घाटन कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इस दौरान जिला परियोजना प्रबंधक श्रीमती रेखा अहिरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा श्रीमती स्वाति सिंह, जिला प्रबंधक कृषि श्री संजय डेहरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रमाशंकर गर्ग, श्री सुदेश भारद्वाज एवं विकासखंड की टीम उपस्थित थी।

बिना ई-टोकन उर्वरक बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

सतना (कृषक जगत)। जिले के किसानों को खाद प्राप्त करने में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने ई-विकास वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली को सख्ती से लागू कर दिया है। अब जिले में मार्कफेड, सहकारी समितियों, एमपी एग्रो और निजी विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरक (खाद) खरीदने के लिए ई-टोकन अनिवार्य कर दिया गया है।

किसान भाई खाद प्राप्त करने के लिए eto-ken.mpkrishi.org वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड के माध्यम से ई-टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन प्राप्त करते समय किसान अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी खुदरा विक्रेता का चयन कर सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना ई-टोकन के किसी भी विक्रेता द्वारा खाद का विक्रय नहीं किया जाएगा।

उप संचालक कृषि विभाग श्री आशीष पाण्डेय ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बिना ई-टोकन के खाद न बेचें। यदि कोई भी विक्रेता इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले के निजी एवं सहकारी थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और कंपनी प्रतिनिधियों को गूगल मीट के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया है। ई-विकास प्रणाली के प्रभावी होने के बाद अब तक जिले के 853 किसानों ने ऑनलाइन टोकन जनरेट किए हैं। इनमें से 813 किसानों ने सफलतापूर्वक 312.295 मीट्रिक टन उर्वरक खरीदा है। जिसमें 297.045 मीट्रिक टन यूरिया, 13.800 मीट्रिक टन डीएपी और 1.450 मीट्रिक टन एसएसपी शामिल है।

मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण से खेती में आयेगी समृद्धि : डॉ. शर्मा

कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक परामर्शदात्री की बैठक

सिवनी

सिवनी (कृषक जगत)। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के अंतर्गत वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन दर्पण सभागार में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया, इस दौरान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. टीआर शर्मा के मुख्य अतिथ्यि में बैठक का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. रजनीश श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक अटारी जोन 9 जबलपुर उपस्थित रहे, साथ ही उपसंचालक कृषि श्री सुधीर कुमार धुर्वे एवं डॉ. शेखर सिंह बघेल वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख मंचासीन रहे। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ ही केंद्र में संचालित विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र में वर्ष 2024-25 में रबी में किए गए कार्यों का डॉ. शेखर सिंह बघेल वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति की गई। एवं आगामी वर्ष 2025-26 में किसान हितैषी विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी एवं परिचर्चा आयोजित की गई।

अटारी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रजनीश श्रीवास्तव, उपसंचालक कृषि श्री सुधीर कुमार धुर्वे ने भी जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं आभार उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉ. निखिल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सहयोग डॉ. राजेंद्र सिंह ठाकुर, इंजी कुमार सोनी, डॉ. केपी एस सैनी का रहा। बैठक में श्री सुधीर कुमार धुर्वे, उपसंचालक कृषि, श्री प्रफुल्ल घोड़ेश्वर, डॉ. मनीश कुमार सेन्डे, पशु चिकित्सा विभाग, श्री कौशल सूर्यवंशी, ईफको, श्री सुनील श्रीवास्तव, बीज निगम, श्री जे. एस. धुर्वे, सहायक यंत्री, श्रीमति संध्या कुमार, मतस्य विभाग, श्री नीरज कुशवाहाएवं श्री अनुपम गौतम, प्रबंधक रिलान्यस फाउन्डेशन, श्री प्रवीण कुमार देसोरिया लीड बैंक, प्रगतिशील किसान श्री शिवराम सनोडीया, श्री अयोध्या प्रसाद भोयर, श्री प्रदीप राहांगडाले वर्मीकम्पोस्ट प्रोड्यूसर, श्री मेहताब सिंह बघेल, ग्रीनवर्मी ड्यूसर कम्पनी, श्री संतोष कुमार पटले की उपस्थिति रही।

वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉ. शर्मा का निधन

भिंड। वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ एवं सेवानिवृत्त असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉ. राधाकृष्ण शर्मा का 13 जनवरी 2026 को हृदय गति रुक जाने से असामयिक निधन हो गया। डॉ. शर्मा एक अनुभवी कृषि विशेषज्ञ होने के साथ-साथ विधि क्षेत्र से भी जुड़े रहे तथा हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में भी सेवाएं दीं। इसके बावजूद उनका मुख्य लगाव सदैव कृषि एवं किसानों के हितों से जुड़ा रहा। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी वे भिंड जिले के ग्रामीण अंचलों में गांव-गांव जाकर किसानों को खेती-किसानी से संबंधित समसामयिक एवं नि:शुल्क सलाह प्रदान कर रहे थे, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

पटवारी एग्रो एजेन्सी
:: वितरक ::
◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि.
◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि.
◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ
◆ डयूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउएग्रो साइंसेस ◆ एग्री सर्च इंडिया
◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी आर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.
17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

कई प्रकार की फसलों के लिए एकमात्र स्वचलित गियर ड्राईव
वरदान
मल्टीक्रॉप पॉवर रीपर
वरदान एग्री सॉल्यूशन्स प्रा.लि.
63, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर-452015 (म.प्र.) फोन: 0731-4970600, 6264916090.

कैरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि., खरगोन
आपकी समृद्धि हमारी प्राथमिकता
हमारे यहां पर ड्रिप में फ्लैट और राउण्ड एचडीपीई व स्प्रिंकलर पाईप, एचडीपीई क्वाइल, लपेटा पाईप एवं रेन पाईप वर्जिन एवं उच्च क्वालिटी में बनाये जाते हैं। सम्पर्क - निरंजन नगर, कसरावद रोड, खरगोन,
मो. : 7880017028, 7880017021
मई 25

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited
NIMADFRESH
यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेराग्लेब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से गठित FPO निमाड़फ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर ODOP - मिर्च-खरगोन
निमाड़फ्रेश FPO (JV) हरिओम भुरे 8964087240
टेराग्लेब FPO बालकृष्ण पाटीदार 9575524408
जुलाई 26

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी
ISO 9001 : 2015 सर्टिफाइड
किसान हाईटेक ग्रीनहाऊस नर्सरी
द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पत्तागोभी, फूलगोभी आदि सब्जी के पौधे टेबल स्टेण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं
सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903
सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्टी पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। संपर्क : मो. : 9407853117, 9407853118, 9407853119, नर्सरी स्थल : ग्राम-सिरलाय, तह.- बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.)
मार्च 25

मध्यभारत की सबसे बड़ी नर्सरी
तिरुपति ग्रीन हाऊस नर्सरी
देश का सबसे बड़ा पौध भंडार औषधीय, फलदार, सजावटी फूलों के पौधे, इनडोर, टिश्यूकल्चर, क्रीपर, बोन्साई, सक्यूलेन्ट्स, केक्टस, हैंगिंग प्लांट, वर्टीकल प्लांट, लकी बैंबू रेंज, फॉरेस्ट्री प्लांट एवं सब्जियों के पौधों की विस्तृत श्रृंखला में
: आपका स्वागत है :
सिरलाय (बड़वाह) मध्यप्रदेश
www. tirupatinursery.com
email : tirupatinursery@gmail.com
मो. : 9479457720/99/63/86/96/16/17/13/31/51
मार्च 2025

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ
व्यक्तिगत क्लासीफाइड
विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-
- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ▪ बीज ▪ औषधीय फसल
विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ▪ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक
डिस्प्ले क्लासीफाइड
विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5%अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.
कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेक्टर्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।
कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर 2026-27 जारी

मध्य प्रदेश में 3.75 लाख करोड़ की क्रेडिट क्षमता

कृषि और MSME पर सबसे ज़्यादा जोर

भोपाल (कृषक जगत)। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने मध्य प्रदेश के लिए स्टेट फोकस पेपर (SFP) 2026-27 पेश किया है। इसमें राज्य के लिए रू. 3.75 लाख करोड़ से अधिक की प्राथमिकता क्षेत्र क्रेडिट क्षमता का अनुमान लगाया गया है। यह दस्तावेज़ कृषि, MSME और ग्रामीण विकास की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इस अवसर पर मिंटो हॉल, भोपाल में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, कृषि मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती, RBI की रीजनल डायरेक्टर सुश्री रेखा चंदनवेली, SLBC संयोजक श्री धीरज गोयल, राज्य सहकारी बैंक के एमडी श्री मनोज गुप्ता, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री विजेन्द्र सिंह, उपमहाप्रबंध श्री सलिल झोकरकर, प्रबंधक द्वय श्रीमती अनविता एवं श्री रवि मेश्राम सहित वरिष्ठ बैंकर और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे।

कृषि और MSME को सबसे ज़्यादा ऋण

स्टेट फोकस पेपर के अनुसार

- कृषि क्षेत्र के लिए रू. 2.08 लाख करोड़
- MSME क्षेत्र के लिए रू. 1.46 लाख करोड़।
- शेष रू. 20,371 करोड़ निर्यात, शिक्षा, आवास, सामाजिक ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए अनुमानित हैं।

नाबार्ड के अनुसार, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका प्रमुख है, जो राज्य के GSDP में 44.36 प्रतिशत का योगदान देती है। इसी कारण कृषि ऋण क्षमता को प्राथमिकता दी गई है। इसमें

फसल ऋण: रू. 1.79 लाख करोड़

कृषि बुनियादी ढांचा: रू. 6,461 करोड़

पशुपालन व अन्य सहायक गतिविधियां: रू. 22,692 करोड़ शामिल हैं।

राज्य गेहूं, चावल, सोयाबीन, चना, दालों और तिलहन के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है, जिससे कृषि ऋण की मांग लगातार बनी हुई है।

राज्य की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग स्थिति

नाबार्ड के अनुसार

- वर्ष 2024-25 में राज्य का GSDP रू. 15.03 लाख करोड़ रहा
- विकास दर 6.05 प्रतिशत
- प्रति व्यक्ति आय रू. 1.52 लाख
- राज्य में 8,779 बैंक शाखाएं और 8,882 ATM हैं
- मार्च 2025 तक क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात 83.51 प्रतिशत रहा।

ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य की बैंकिंग व्यवस्था भविष्य की बढ़ती ऋण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

वार्षिक क्रेडिट योजना को मिलेगी दिशा

स्टेट क्रेडिट सेमिनार के जरिए नाबार्ड का उद्देश्य ACP 2026-27 को अंतिम रूप देना है, ताकि कृषि, MSME और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो सके।

नाबार्ड ने स्पष्ट किया कि वह डिजिटल बैंकिंग, ग्रामीण ढांचा, सहभागी योजना और समावेशी विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश में स्थायी ग्रामीण समृद्धि के लिए लगातार काम करता रहेगा।

ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका

नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती ने बताया कि-

- 2024-25 में रू. 27,331 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई।
- रू. 4,132 करोड़ RIDF के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए।
- रू. 23,199 करोड़ ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त के रूप में।

इसके अलावा,

- 90 वाटरशेड परियोजनाएं (95,404 हेक्टेयर क्षेत्र)।
- 103 आदिवासी विकास परियोजनाएं, जिससे 78,000 से अधिक परिवारों को लाभ।
- 426 किसान उत्पादक संगठन (FPO), जिनसे 2.26 लाख किसान जुड़े।
- 4,535 PACS का कम्प्यूटरीकरण, जिससे मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।

जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ का महा अधिवेशन हुआ

इंदौर (कृषक जगत)। जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ, इंदौर द्वारा गणतंत्र दिवस पर वार्षिक जिला स्तरीय महा अधिवेशन केट रोड,इंदौर स्थित एक रिसार्ट में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन नई दिल्ली से सम्बद्ध संस्था के पदाधिकारीद्वय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मानसिंह राजपूत,राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय रघुवंशी एवं पूर्व विधायक श्री संजय शुक्ला थे। इस आयोजन में श्री लेखराज खत्री (उज्जैन), जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर के अध्यक्ष श्री कृष्णा दुबे,उपाध्यक्ष श्री पूनम हार्डिया, सचिव श्री जितेंद्र जैन सहित अन्य पदाधिकारी,कृषि विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आदान विक्रेता उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री राजपूत ने कहा कि कृषि व्यवसाय का अस्तित्व खतरे में है। अब सरकार पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। आपने बताया कि कीटनाशक बनाने वाली अनेक बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों एवं किसानों को कीटनाशक भेजने का कार्य कर रही है, जो पूर्णत: गलत है, क्योंकि इनके पास प्रिंसिपल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होते हैं। इन कंपनियों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाना चाहिए। श्री शुक्ला ने कहा कि मेरा परिवार कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है एवं समय-समय पर आपके कार्यक्रमों में आने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मैं आपके परिवार का ही सदस्य हूं। श्री रघुवंशी ने कृषि व्यवसायियों को अपने व्यवसाय में आने वाली कानूनी समस्या एवं उनके निदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। आपने खाद, बीज और कीटनाशक के नमूने फेल होने पर व्यापारियों को बचाव के उपाय एवं अन्य कानूनी जानकारियां दी। आपने ई-टोकन प्रणाली और सीड एक्ट पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन के पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल के विरोध में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने पर संघ के सदस्यों को ही लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम के आरम्भ में अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष श्री कृष्णा दुबे, उपाध्यक्ष श्री पूनम हार्डिया, सचिव श्री जितेंद्र जैन एवं पदाधिकारी श्री अजय गुप्ता, श्री सूरज गुप्ता, श्री अभिषेक दुबे एवं श्री चंद्रप्रकाश जैन के द्वारा किया गया। इस मौके पर श्री दुबे ने कहा कि म.प्र. कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल एवं ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन, नई दिल्ली के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन से हम अपने संगठन को इंदौर जिले की अनेक तहसीलों में स्थित विक्रेता बंधुओं को संगठन से जोड़ पाए हैं। कार्यक्रम में विशेष बीमारी से पीड़ित बालिका अनिका को जागरूक आदान विक्रेता संघ इन्दौर की ओर से तत्काल एक लाख रुपए देने की घोषणा की गई। कृषि विभाग से श्री सत्यनारायण जाट एवं श्री मालवीय उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह श्री कमल बिरला, श्री किशोर पुराणिक, श्री विनोद चौहान एवं श्री सुनील पाटीदार के द्वारा भेंट किए गए। संचालन श्री आशीष लाठी ने एवं आभार श्री जितेन्द्र जैन द्वारा व्यक्त किया गया।

ड्रोन दीदी रूपाली को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

उज्जैन (कृषक जगत)। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 26 जनवरी 2026 को पहली बार 'लखपति दीदी' थीम पर मिशन अंतर्गत विभिन्न जिलों में झांकी प्रदर्शित की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलों में आयोजित समारोहों में प्रदर्शित

की गई इन झांकियों में अधिकांश जिलों को पुरस्कार मिले हैं। उज्जैन जिले में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तराना विकासखण्ड के डबलाहरदू ग्राम की ड्रोन दीदी श्रीमती रूपाली मोदी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए मंच से सम्मानित किया।

जिलों द्वारा झांकी प्रदर्शन किया गया - 38 जिलों द्वारा इसी विषय पर झांकी निकाली गई। इसमें से 10 जिलों ने प्रथम स्थान, 7 जिलों ने द्वितीय एवं 7 जिलों ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिलों में खरगोन, सिंगरौली, पन्ना, ग्वालियर, कटनी, नीमच, सतना, मैहर, शहडोल एवं बालाघाट शामिल हैं। द्वितीय पुरस्कार रायसेन, उज्जैन, मुरैना, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास एवं रतलाम जिले ने हासिल किया है। तृतीय पुरस्कार सीहोर, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, छतरपुर, इंदौर एवं हरदा जिले ने प्राप्त किया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी आजीविका मिशन श्रीमती हर्षिका सिंह ने जिलों में प्रदर्शित होने वाली झांकियों में मिशन अंतर्गत 'लखपति दीदी' थीम को शामिल करते हुए झांकी प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया था।

भरपूर उर्वरक के दावे और जमीनी हकीकत!

● मधुकर पवार, मो.: 8770218785

प्रश्न यह नहीं है कि उर्वरक कितना उपलब्ध था, बल्कि असली सवाल यह है कि फिर किसानों को समय पर खाद क्यों नहीं मिली? क्यों उन्हें कई-कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा और रात-रात भर उर्वरक वितरण केंद्रों के बाहर कतारों में खड़ा रहना पड़ा?

जब दावे और ज़मीनी हकीकत टकराए

सरकार का कहना है कि भारतीय रेलवे ने उर्वरक रैकों की ढुलाई को प्राथमिकता दी, बंदरगाहों पर आयातित उर्वरकों की त्वरित अनलोडिंग हुई और भंडारण व वितरण की व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई। उर्वरक कंपनियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों और सतत निगरानी के दावे भी किए गए। यदि ये सभी व्यवस्थाएँ वास्तव में प्रभावी थीं, तो फिर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों में किसानों को खाद के लिए भटकना क्यों पड़ा?

खरीफ-रबी दोनों में संकट

हकीकत यह है कि खरीफ और रबी-दोनों ही मौसमों में किसानों को उर्वरक की भारी किल्लत झेलनी पड़ी। कई स्थानों पर कालाबाजारी की खबरें सामने आईं और मजबूरी में किसानों को निजी दुकानों से अधिक कीमत चुकाकर खाद खरीदनी पड़ी। विडंबना यह है कि इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकारें लगातार यह दोहराती रहीं कि 'खाद की कोई कमी नहीं है।'

समस्या कहाँ है?

जब वास्तव में खाद की कोई कमी नहीं थी, तो फिर किसानों तक खाद पहुँचाने में देरी क्यों हुई? यह विरोधाभास साफ संकेत देता है कि समस्या उत्पादन या आयात की नहीं, बल्कि परिवहन, भंडारण और वितरण तंत्र की गंभीर विफलता की है। यदि उर्वरक आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध था, तो उसे समय पर सभी जिलों और ब्लॉकों तक पहुँचाने में लापरवाही क्यों बरती गई?

केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि वर्ष 2024-25 में देश में उर्वरकों की रिकॉर्ड उपलब्धता सुनिश्चित की गई और किसानों को पूरे वर्ष किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहाँ देश की अनुमानित आवश्यकता 152.50 करोड़ बैग (722.04 लाख टन) थी, वहीं 176.79 करोड़ बैग (834.64 लाख टन) उर्वरक उपलब्ध कराया गया—अर्थात् आवश्यकता से लगभग 24 करोड़ बैग अधिक।

जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई?

क्या यह प्रशासनिक उदासीनता नहीं है कि गोदामों में उर्वरक भरा रहा और किसान बोनी के समय खाद के लिए तरसता रहा? इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा। जिन जिलों में खाद की कमी रही और समय पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया गया, वहाँ संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। लेकिन हर बार की तरह इस व्यवस्था-विफलता को आंकड़ों की आड़ में ढंक दिया गया।

तकनीक के दौर में भी लाइन में किसान

सरकार डिजिटल पोर्टल, आधुनिक संचार माध्यमों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि किसान आज भी खाद के लिए लाइन में खड़ा होने को मजबूर है। तकनीक के इस दौर में भी यदि किसान उर्वरक के लिए दर-दर भटक रहा है, तो यह पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।

समाधान क्या हो?

समाधान केवल नए दावे करने में नहीं, बल्कि मांग-आधारित वितरण प्रणाली, जिला-ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य न्यूनतम स्टॉक, और वितरण से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करने में है। सहकारी समितियों और एफपीओ को मजबूत कर निजी मुनाफाखोरी पर प्रभावी रोक लगानी होगी। सबसे अहम यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी दावे खेत की मेड़ पर भी सच साबित हों।

आखिरी सवाल

किसान को यह भरोसा मिलना चाहिए कि बोनी के समय उसे खाद के लिए अपमानजनक कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जब तक उर्वरकों की 'रिकॉर्ड उपलब्धता' समय पर किसानों के हाथों तक नहीं पहुँचती, तब तक ऐसे दावे केवल सरकारी कागज़ों की उपलब्धि बनकर ही रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को अब उर्वरकों की उपलब्धता, मांग, परिवहन, भंडारण और वितरण की समग्र समीक्षा कर पिछली कमियों को दुरुस्त करना होगा, ताकि आने वाले खरीफ और रबी के मौसम में किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध हो सके।